

जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स एम.एल नम्बर 08/2012 खनन क्षेत्रफल 1260.96 हेक्टेयर निकटग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित जनसुनवाई दिनांक 26 मई 2025 समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक का कार्यवाही विवरण :-

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025, 18553 दिनांक 02.05.2025 एवं 18617 दिनांक 07.05.2025 (संलग्नक-अ) की अनुपालना में दिनांक 26 मई, 2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान में मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स एम.एल नम्बर 08/2012 खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक राजस्थान द्वारा रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला-टोंक राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयी:-

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक, जिला टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी
3. श्री कपिल शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
4. श्री राहुल पारीक, तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी व अन्य लोगों का उपस्थिति-पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचारपत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 01.04.2025, 05.05.2025, 08.05.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "टोंक भास्कर" में दिनांक 01.04.2025, 05.05.2025, 08.05.2025 को आमसूचना निर्धारित जनसुनवाई से नियमानुसार निर्धारित समय (दिवस) पूर्व

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

102
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं (संलग्नक-स)। जनसुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग डी.वी.डी./ पेन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ संलग्न हैं (संलग्नक-द)।

श्री राम रतन सौकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक द्वारा सभाकक्ष में उपस्थित नागरिकों का स्वागत करते हुए जनसुनवाई की शुरुआत की गई। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह एक लीगल प्रोसीजर है कि जब भी कोई आवेदक पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन करता है तो एक अनिवार्य पार्ट है कि जनसुनवाई करके वहां की जनता वहां के, जनप्रतिनिधि, वहां के लोग के आवेदन प्रति क्या विचार हैं, क्या आपत्ति है, यह जानना होता है। मुलतः यह जनसुनवाई पर्यावरण विभाग की है प्रशासन का इन्चॉल्वमेन्ट इसलिए रखा गया है कि इस जनसुनवाई में अपनी बात प्रमुखता से रख सकें और जो भी बात उन्होंने रखी वो हुबहु प्रोसिडिंग (कार्यवाही विवरण) में आ जाये। इसलिये प्रशासन को जनप्रतिनिधि व लोग इस जन सुनवाई में आये वों अपनी बात प्रमुखता से रख सकें ओर उन्होंने जो बात रखी हैं वे हूबहू उसकी प्रोसिडिंग में आ जाए इसलिए प्रशासन को इन्चाल्व रखा हैं। अन्यथा पूरी तरह यह कार्य पर्यावरण डिपार्टमेन्ट का है। तो हम यहां पर प्रशासन के ओर एस.डी.एम, तहसीलदार साहब भी उपस्थिति हैं। हम आपकी बात को प्रमुखता से यहां पर रखें और आप जो बात रख रहे हैं वो रिकॉर्ड में चली जाये। यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति हैं। उन्होंने जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक परियोजना के बारे में जानकारी दें कि उनका क्या प्रस्ताव हैं, उस प्रस्ताव के क्या योजना हैं। हम उसको ध्यान से सुनेंगे, उनके बाद में जिस बिन्दु पर हमारी कोई भी आपत्ति हैं तो उसके बारे में पुछेंगे लेकिन पहले इनकी प्रेजेन्टेशन समाप्त होने दे। उसके बाद एक-एक करके अपनी बात रखें, आपत्ति कर सकते हैं। कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बात कहने वाले व्यक्ति की पहचान बताना भी जरूरी होता हैं। अतः आप पहले अपना नाम बतायेंगे, पिताजी का नाम फिर एक-एक कर अपनी बात कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया की विडियो ग्राफी भी करायी जा रही हैं, आप जो बात कहेंगे हम उसे नोट भी करेंगे की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अधिकारी को सुनवाई की कार्यवाही करने के लिए आमंत्रित किया।

श्री राम रतन सौकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक की अनुमति से श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने उपस्थित जन-समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते हैं।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकॉर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक (राज०)

नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को रिवरबेड सेण्ड (माईनर मिनरल) खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात् मैसर्स श्री चांडक एसोसिएट्स, के सलाहकार मैसर्स गोरंग इन्वायरमेन्टल सोल्यूषन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से श्री अनिल अग्रवाल ने रिवरबेड सेण्ड खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार के बारे में उपस्थित जनसमूह को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमें परियोजना का विवरण, खनन पट्टे के स्थान, खनन पट्टे की अवधि, खनन पट्टा क्षेत्र, भूमि का विवरण, मूल व्यवस्था, खनन का विवरण, खनन की विधि, खनिज, संभावित खनिज भंडार, खनन योग्य भंडार, लक्षित उत्पादन, खनन कार्य की अधिकतम सीमा, भू-जल तालिका, खनन पट्टा स्वीकृति आदेश, संशोधित खनन योजना, परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ, परियोजना स्थल का मानचित्र, परियोजना स्थल की गूगल छवि, खनन विवरण, भूमि उपयोग वर्गीकरण, 10 किमी टोपोशीट, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय बेसलाइन अध्ययन का विवरण, 10 किलोमीटर त्रिज्या अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग/भूमि करव मैप, अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग विभाजन, बेसलाइन अध्ययन विवरण, चयनित जाँच स्थल, 10 किलो मॉनिटरिंग टोपोशीट, पर्यावरणीय बेसलाइन अध्ययन परिणाम, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, ठोस और हैजड्स अपशिष्ट प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन, हरित पट्टी का विवरण, हरित पट्टी का विकास बफर जोन का जैव विविधता प्रोफाइल, अध्ययन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय की रूप रेखा, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, सामाजिक पर्यावरण, प्रस्तावित परियोजना के लाभ के बारे में जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, ने उपस्थित जनसमूह को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया। उपस्थित जन-समूह द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाही गयी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा जनसुनवाई की प्रक्रिया के बारे में पुनः संक्षिप्त में जानकारी दी गयी।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा पूछा गया कि कल तक तो जनसुनवाई ग्राम बरवास में था। आज मैं टोडारायसिंह में हो गया। इस कोई प्रचार ही नहीं है। हम सरपंच हैं, हमें ग्राम बरवास में पता थी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आम सुचना अखबार के माध्यम से प्रसारित की गयी व मुनादी भी

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

२५/११/२०१९

कराई गयी। समाचार पत्रों में जनसुनवाई का स्थान टोडारायसिंह पंचायत समिति कार्यालय ही था।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा पुछा कि अन्दर इस मीटिंग/जनसुनवाई में कौन आ सकता है ?

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा अवगत कराया गया कि यह एक जनसुनवाई है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने सुझाव दिया कि अगर आप ग्राम बरवास में जनसुनवाई रख लेते तो हम प्रेक्टिकल रूप से नदी को देख भी लेते।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- ने अवगत कराया कि जन सुनवाई का दिन, समय व स्थान नियमानुसार पूर्व में सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपका यह सुझाव नोट कर लिया गया है। कार्यवाही विवरण के साथ सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जायेगा।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने कहा कि अगर मैं कोई बात कहूँ और आप उस बात को नहीं माने तो मैं चाहता हूँ कि आप मौका पर नदी का निरीक्षण करे प्रेक्टिकल रूप से खनन गतिविधि को देख भी लेंगे। दुध का दुध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को पुछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- ने अवगत कराया कि आप जो बात कहेंगे हम उसे नोट करेंगे/लिखेंगे। आपका कहना है कि मौका निरीक्षण किया जाए हम उसको भी नोट करेंगे व जनसुनवाई कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करेंगे। आप जो भी कहेंगे हम उसे अक्षरशः जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण सम्मिलित करेंगे। अगर कुछ लिखित में भी देना चाहे तो हम उसे भी जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करेंगे।

श्री राम रतन साँकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:- ने अवगत कराया कि आप चाहते हैं कि मौका निरीक्षण किया जाए। हम लिख रहे हैं कि मौका निरीक्षण की मांग की गयी व कार्यवाही विवरण में सम्मिलित किया जाएगा। मौका निरीक्षण के लिए सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाएगा तथा जिसको भी सक्षम स्तर से मौका निरीक्षण के लिए निदेशित किया जाएगा। वह मौका निरीक्षण करने आएगे।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- हम किसी के विरोधी नहीं हैं लेकिन यह भी नहीं है हम जिन्दी मक्खी निगल जाए। उन्होंने पुछा कि इस जन सुनवाई में पार्टीसिपेंट (हिस्सा) कोन ले सकता है/कौन अधिकृत है, यहा आने के लिए ? यह बैठे 20 आदमी निर्णय लेंगे क्या ? और आप इसे मान जाओगे क्या ? कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि 20 आदमी वो भी बाहर के आकर पर्यावरण को तय कर देंगे कि बजरी खनन कर लिया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं, वह प्रभावित गाँवों से नहीं हैं। उन्होंने उपस्थिति लोगों से उनके गाँव का नाम पुछा। उन्होंने फिर कहा कि ग्राम सेतीवास से कोई नहीं आया, छान से कोई नहीं आया, मोर भाटियान से कोई नहीं आया। ठाठा से कोई नहीं आया, रामपुर से कोई नहीं आया। उन्होंने बताया कि यह खनन परियोजना 17 गाँवों में फैली है व इन गाँवों से कुल

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला नजिस्ट्रेट

टोंक (राज०)

मिलाकर भी 17 लोग इस जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप जो उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करा रहे हो, उस पर नाम पते भी लिखवाओं, कौन से गाँव से आये हैं।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- ने उत्तर दिया कि उपस्थिति पत्रक में पता/गाँव का नाम अंकित करवाए जा रहें हैं।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- आप महरबानी करके जनसुनवाई को निरस्त कर दीजिए। नदी के किनारे जनसुनवाई कराओ। वहां के लोगों को बुलाएंगे।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:- ने अवगत कराया कि आप लोगों की मांग है कि इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाए तो हम यही बात कार्यवाही विवरण में लिखेंगे।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- अगर कोई लोग इस परियोजना से प्रभावित है तो इस जनसुनवाई में आ सकते थे, मना किसने किया है।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- जन सुनवाई का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। इसे तो पता ही नहीं था इस जनसुनवाई का। आपने (श्री रामचन्द्र सेतीवास) ने बताया तो पता लगा और हम यहां आये।

उन्होंने ग्राम छानवाससूर्या, बरवास, एवं ग्राम चुली के खसरा संख्या का उल्लेख करते हुए सीमाज्ञान नही होने की बात कही। उन्होंने बताया की 4 माह पूर्व SDM एवं AME साहब दोनों को मैंने नदी में बुलाया था एवं उन्होंने आश्वासन दिया था कि 07 दिन में सीमाज्ञान कर देंगे लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि प्रत्येक 1000 मीटर के ब्लॉक के बाद जिसके उपर खनन किया जाता है, 50 मीटर की बफर दूरी गैर-खनन ब्लॉक या नियामक प्रधिकरण द्वारा निर्धारित दूरी बनायी रखी जाएगी जबकि मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकुछ सपाट कर दिया गया है कोई बफर नहीं है।

उन्होंने कहा कि इन्होंने (परियोजना प्रस्तावक) बताया कि दोनों तरफ के प्रमुख पुलों और राजमार्ग से 1 किलोमीटर के दायरे में रेत और बजरी निकालना प्रतिबन्धित होगा जबकि मौके पर ऐसा नहीं है। उन्होंने पुनः मौका निरीक्षण हेतु प्रस्ताव रखा।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:- ने बताया कि हमने आपकी बात लिख ली है। एवं कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करते हुए सक्षम स्तर तक पहुँचाएंगे। सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तथा यदि वह मौका निरक्षण कराना चाहते हैं तो विषय विशेषज्ञ से निरीक्षण करवायें।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- इन बजरी खनन वालो ने गाँव में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। कि आने वाले 20 वर्षों में भी लोग आपस में बातचीत नही करेंगे। पूरे गाँव में टुकडे करा दिये है। खनन कार्य करने वाले सभी लोग बाहरी है। एक भी स्थानीय व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है।

NO

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा पुछा गया कि इस जनसुनवाई में बाहर के लोग क्यों आये हैं ? लीज वालों की तरफ से दो पाँच लोग आ सकते हैं बाकी लोग क्यों आये हैं ? यह जनसुनवाई गाँव में चाहिए थी।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जनसुनवाई के सम्बन्ध में नियमानुसार एक स्थानीय समाचार पत्र टोंक भास्कर व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डिय एक्सप्रेस" में आम सूचना निर्धारित समयावधि में प्रकाशित करवाई गई।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई है एवं हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति इस जनसुनवाई में भाग ले सकता है।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा पुछा कि यह जनसुनवाई क्यों की जा रही है व किसके लिए की जा रही है।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा अवगत कराया गया कि यह जनसुनवाई मै0 चाण्डक एसोसिएट द्वारा 17 गाँवों में प्रस्तावित खनन क्षमता विस्तार हेतु आयोजित की गयी है। इस जनसुनवाई में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इस जनसुनवाई में इस परियोजना से प्रभावित व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। मौखिक या लिखित किसी भी रूप में। जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करते हुए सक्षम स्तर को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गयी मुनादी की फोटो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाई गयी।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा पुछा कि जनसुनवाई की अवधि क्या है? उनके द्वारा कहा गया कि सही फैसला लिजिए।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा अवगत कराया गया आप जब तक आपत्ति दर्ज कराते रहेंगे, हम आपत्ति दर्ज करते रहेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि हम इस जनसुनवाई में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम आप लोगों की बात को इस जनसुनवाई के माध्यम से सक्षम स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने अवगत कराया कि पूरा देश जानता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। आप के हाथ में कलम है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ईमानदारी से फैसला करना।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- यहां पर हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं। उसे हम नोट कर रहे हैं हम यहां आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। जो आप बोल रहे हैं सषब्द मिटिंग मीनेट्स (कार्यवाही विवरण) में लिखा जाएगा।

श्री राम चन्द्र, ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- मिटिंग मीनेट्स में जाएगा हमें पता है, लेकिन न्याय करो। जस्टिफिकेशन करो।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:— हम यहां आपकी बात सुनने आये हैं व आपकी बात को सक्षम स्तर तक पहुंचाने के लिए आये हैं। हम यहां कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:— द्वारा पुछा गया कि क्या यह जनसुनवाई सही है? क्षेत्रीय अधिकारी साहब द्वारा बताया गया कि यह जनसुनवाई निर्धारित **E.I.A Notification** के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार करायी जा रही है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:— ने कहा कि जन सुनवाई में 10 गाँव के लोगो का आना अनिवार्य हैं। कोई 05 आदमी बाहर के आकर कह देंगे तो मान जाओगे क्या ? इतना बड़ा काम जिससे देश चलता हैं। हजारो लाखों पौधे लगाकर हम जिन्दा रखते हैं लोगों को, इन्सान व पौधे दोनो एक सम्मान है। दोनों प्रकृति की देन है।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:— प्रधान साहब आप जन प्रतिनिधि हो, पूरी पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं। कि पूरी पंचायत समिति के लोग यहां बैठे हैं। हम यहां कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप जो कहेंगे हम उसे नोट करेंगे, आप अच्छा कहेंगे हम अच्छा लिख देंगे आप बुरा कहेंगे बुरा लिखेंगे तथा कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करके सक्षम स्तर को प्रेषित करेंगे। आप जो कहेंगे उसके अलावा अगर कुछ लिख दिया तो आप बता देना कि यह तो हमने कहा ही नहीं और आपने लिख दिया या आप जो बोल रहे हैं उसमें से कोई बात कार्यवाही विवरण में नहीं की जाये तो बता देना।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:— ने जनसुनवाई निरस्त करने हेतु कहा कि आप तो आप जन सुनवाई निरस्त करीये अगली बार जनता जनसुनवाई में आएगी।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:— ने अवगत कराया कि जन सुनवाई की कार्यवाही विवरण में लिखेंगे कि जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की गयी।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:—ने कहा कि ये 17 के 17 गाँव हमसे सम्बन्धित है, हम दो आदमी बैठ के उनका निर्णय कर दे यह तो गलत है। रहना तो हमे वही है, इसलिए कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। और बैठक आप इन लोगों की उपस्थिति में कराओगे तो यह जस्टिफिकेशन नहीं है। न्याय नहीं क्योंकि ये लोग (Absolutely Outsides) बिल्कुल बाहरी हैं। They are not coming from that Area. ये लोग उस क्षेत्र से नहीं आते हैं। जो लोग वांछनीय है, अगली बार आप चाहोगे जैसे कर देंगे। जनसुनवाई के लिए वहां की जनता का होना आवश्यक हैं। अतः जन सुनवाई मान्य नहीं है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:—ने उपस्थित जन समुदाय का परिचय लेने हेतु बात कही। एवं स्वमं का परिचय दिया कि मै0 रामचन्द्र ग्राम सेतीवास से आया हूँ। तत्पश्चात श्री राम दयाल गुर्जर, ग्राम छानबाससूर्या, तहसील टोंक द्वारा अपना परिचय दिया गया। श्री भेरूलाल शर्मा ग्राम बोटून्दा द्वारा अपना परिचय दिया गया।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:— द्वारा अवगत कराया गया कि यह खनन परियोजना बोटून्दा गाँव में नहीं है। प्रधान द्वारा पुनः मौका निरीक्षण हेतु आग्रह किया गया।

NAL


क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक, राजस्थान

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक:- द्वारा अवगत कराया गया कि आप इस जनसुनवाई में जो कहेंगे उसे नोट करेंगे। व कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करेंगे।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- द्वारा अवगत कराया कि इस बजरी खनन पट्टाधारी द्वारा कोई वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया, एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने अवगत कराया कि छानवाससूर्या व बरसवा का नदी में कोई सीमांकन नहीं है। नदी के पानी से बजरी निकाली जा रही है। एवम इनके द्वारा उत्पादन सम्बन्धी जानकारी चाही गयी। उन्होंने पूछा कि क्या नदी के बहाव को खनन हेतु रोका जा सकता है।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- ने बताया कि उत्पादन सम्बन्धित लेखा व जोखा, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा संधारित किया जाता है। एवम् खनन करने से पहले खनन पट्टाधारी को माईनिंग प्लान, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा अनुमोदित कराना होता है। तथा खनन अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार करना होता है। यदि खनन पट्टाधारी माईनिंग प्लान के अनुरूप खनन नहीं करता है, तो खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- इनका माईनिंग प्लान अनुमोदित हो गया है। यह पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई है। माईनिंग की जानकारी माईनिंग विभाग देगा। माईनिंग का क्षेत्राधिकार उनका है।

श्री राम चन्द्र ग्राम सेतीवास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मेरा दायित्व है कि जनता का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से करूँ। पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अधिकारी योग्यता से बनते हैं। जनप्रतिनिधि जनता के वोट से बनते हैं। आपकी ड्यूटी बनती है, ईमानदारी से जस्टिफिकेशन करो। उन्होंने कहा कि आज की जनसुनवाई वाजिव नहीं है, जन सुनवाई को निरस्त करते हुए पुनः जन सुनवाई की जाए और उसमें बैठकर निर्णय लिया जाएगा। आप चाहे तो करा देगे भले ही लेकिन यह जनता के लिए सही नहीं है, कल को लोग हमें गाली देगे कि आपने कैसे फैसला कर दिया। जनसुनवाई में कम से कम 100-200 लोग तो आने चाहिए।

श्री राम दयाल गुर्जर ग्राम छानवाससूर्या, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- नदी में गहरे-गहरे खड्डे हैं। जाकर देख लो। नदी किनारे जगह छोड़ने की बात कही वह सही नहीं है। नदी किनारे 20 से 25 मीटर जगह छोड़ने का दायरा था कोई नहीं छोड़ा।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, कोई आपत्ति दर्ज कराना तो वह स्वतंत्र है, वह अपनी बात कह सकते हैं। यहां पर उन गाँव से भी व्यक्ति उपस्थित है, जिन गाँव से यह परियोजना प्रस्तावित है। अतः आप से लोग भी आपने विचार रख सकते हैं।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक (राज०)


क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

श्री मनोज कुमार चंगल, निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- ने अवगत कराया कि बजरी खनन परियोजना से प्रभावित 17 गाँव में से केवल 05 से 07 लोग ही इस जन सुनवाई में उपस्थित हैं।

श्री रणजीत सिंह, ग्राम गेदिया, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:-ने कहा कि यह अन्य व्यक्ति भी उपस्थित है जो उन्ही प्रभावित 17 गाँव से हैं आप उनका परिचय लें। तत्पश्चात् कुछ अन्य लोगों ने भी अपना परिचय दिया।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बून्दी:- ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से बात पुनः आग्रह किया कि यदि अन्य कोई व्यक्ति अपनी इन परियोजना के लिए स्वतन्त्र है। उसी के साथ ने सभी का धन्यवाद करते हुए जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की।

उक्त जनसुनवाई के दौरान निम्न प्राप्त लिखित आक्षेप/ आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिनकी प्रति संलग्नक हैं (संलग्नक-प्र)।

क्र.स.	व्यक्ति संख्या	प्राप्ति दिनांक	विषय
1.	Yogesh Kumar, 303, Sufal Apartment, Sawai Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur (Rajasthan)	26.05.2025	Objection in Public hearing scheduled 26.05.2025 regarding grant of Environment Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 TPA to 8.2 million TPA (ROM)
2.	जय सिंह नरुका, निवासी ग्राम-खेरड़ा, तहसील-टोडारायसिंह, जिला-टोंक	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
3.	मनोज कुमार चंगल, निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक:- मो. नं. 9929972733	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
4.	रामदयाल गुर्जर S/o रामकरण जी, ग्राम-ईस्लामपुरा पो0 बरवास, तहसील - टोडारायसिंह, जिला- टोंक	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
5.	लियाकत अली, स्वतंत्र पत्रकार, मो0न0 7014653770	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
6.	समीर-उर-रहमान, सेय्याहो की गली- काफला बाजार (टोंक) मो.नं- 7737363738	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।

ML

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान

7.	नाम- केशवराज सैन, पता-न्यू महावीर नगर, रजके वाले बाबा की गली, टोंक (राज.) मो0नं0 7014471095	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोक सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज करने बाबत्।
8.	जिला परिषद सदस्य, ग्राम रलावता, EX-मण्डल अध्यक्ष मोर BJP रलावता, (सरपंच) बरवास, कालराम सैठीवांस, छीतर रलावता, हंसराज, मोडसा, पूर्व सरपंच मोर भाटियान, राजेश मीण मण्डल अध्यक्ष, BJP मोर,दिलराज गुर्जर मोडियाला, मनोहर लाल गुर्जर जैथल्या, बाबूलाल मीणा, (प्रशासक बरवास)	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
9.	श्रीमति सन्तरा देवी गुर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत छाण बास सूर्या, तहसील - टोडारायसिंह, जिला- टोंक	27.05.2025	नियमों के विरुद्ध अवैध खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बाबत्।
10.	शिला राजकुमार मीणा प्रशासन, ग्राम पंचायत बोटून्दा, प0स0- टोडारायसिंह, जिला- टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में जन सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
11.	निर्मला देवी बैरवा, प्रशासन, ग्राम पंचायत-मोरभाटियान, प0स0- टोडारायसिंह, जिला- टोंक मो.न.-9414579738	27.05.2025	बनास नदी में बजरी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने बाबत्।
12.	गायत्री देवी शर्मा, प्रशासक, ग्राम पंचायत खरेडा, पं.स. - टोडारायसिंह (टोक)	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।
13.	श्रीमति सन्तरा देवी, प्रशासक, ग्राम पंचायत बस्सी, पं0स0- टोडारायसिंह जिला टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक (राज०)

			करने बाबत।
14-	रामपाल गुर्जर, उप प्रशासक, ग्राम पंचायत - कंवरावास, पं0स0 -टोडारायसिंह जिला टोंक	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
15	ग्रामवासी ग्राम रलावता, बरवास, सैतीवास, मोर भाटियान, मोडियाला, आदि।	27.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
16	श्रीमती सीता देवी गुर्जर, प्रधान पंचायत समिति टोडारायसिंह	26.05.2025	मै0 चाण्डक एसोसिएट्स एम.एल. द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़कर 8.2 मिलियन को टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।

अन्तः में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित सभी
जन-समुदाय को धन्यवाद करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला टोंक की अनुमति से
लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

(राम रतन सौकरिया)
अति० जिला कलक्टर टोंक,
जिला-टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

Pankaj
7/5/25
JEE(P)
07/05/2025
संलग्न 'अ'

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- / न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617

दिनांक:-07/05/2025

संशोधित आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18572 दिनांक 05.05.2025 से टोंक जिले में स्थित ग्राम कुरासिया, बनेड़िया चाणणान, कंवरवास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाण बाससूर्या, बरवास एवं चूली ग्राम में बनास नदी से रवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पदान क्षमता बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 26.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय उपतहसील बरवास में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यालय उपतहसील बरवास के स्थान पर पंचायत समिति सभागार टोडारायसिंह में नियत की जाती है।

(राम रतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक:- / न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18618-28

दिनांक:-07/05/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रेट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह/टोंक।
3. तहसीलदार टोंक/टोडारायसिंह।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. श्री जितेन्द्र सिंह नरुका, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
8. मैसर्स चाण्डक एसोसियट्स।



(राम रतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

JEE CP
(8)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:-/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553

दिनांक:-02/05/2025

आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 से टोंक जिले में स्थित ग्राम कुरासिया, बनेड़िया चाणणान, कंवरावास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाण बाससूर्या, बरवास एवं चूली ग्राम में बनास नदी से रवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पदान क्षमता बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 03.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति सभागार टोडारायसिंह में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

(राम रतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक:-/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18554-63 दिनांक:-02/05/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्टर, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह/टोंक।
3. तहसीलदार टोंक/टोडारायसिंह।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. मैसर्स चाण्डक एसोसियट्स।

(राम रतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

26/03/25
JEECDM
26/3/2025

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई /2025/14341

दिनांक 25/03/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषय:- Public hearing for Environment Clearance for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील टोडारायसिंह में स्थित ग्रामों में रिवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:-

क्र०सं०	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 3198 दिनांक 18.03.2025 चाण्डक एसोसियट्स	कुरासिया, बनेड़िया चाणनान, कंवरवास, चांदपुरा, सालग्यावास, गोलेड़ा, रलावता, ठाठा, सेंतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोडियाला, छाणबाससूर्या, बरवास, चूली	पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह में दिनांक 03.05.2025 प्रातः 11.00 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई /2025/14342-50 दिनांक 25/03/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्टर, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह।
3. तहसीलदार टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबंधित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर पंचायत समिति सभागार में आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरुका, वरिष्ठ सहायक न्याय अनुभाग कलेक्टर टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत.....।



JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWALI

Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date : 25-03-2025 01:54:43

मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनरल) खनन परियोजना एम.एल संख्या 8/2012 (लीज क्षेत्र 1260.96 हैक्टेयर) प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनरल) कुल उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) निकट ग्राम कुरास्या, बनेड़िया चारणान, कँवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरड़ा, मोडियाला, छानमयबाससुर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 26.05.2025 को प्रातः 11:00 AM बजे, पंचायत समिति सभागार, टोड़ारायसिंह, तहसील-टोड़ारायसिंह, जिला-टोंक में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रक :-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkaria	ADM, Tonk.	ML
2	Shiv Kumar	Regional Officer, RSPCB, Bundi	Shiv
3	CAPIE Akhane	SDM - Toda	CAPIE
4	RAHUL PARGOK	TDR - Toda	RAHUL
5	SAMEER UR- PERMAN	Tonk	Sameer
6	Om Babash Sharma	Auth. Person, Perse owner	Om
7	Yagya Pratap Singh	Leasee	Yagya
8	केशवराय शर्मा	पत्रकार, टोंक (पत्रकारिता)	केशव
9	yudhishthir Singh	सुपरवाइजर	yudhishthir
10	रामेश्वर शर्मा	डीप्टी	रामेश्वर
11	सुरेश गुर्जर	हमीरपुर	सुरेश
12	शालीग्राम यादव	रतनपुरा	शालीग्राम
13	देवराज गुर्जर	रतनपुरा	देवराज
14	शंकर शर्मा	गार्डियन	शंकर
15	उदय शर्मा	देवली	उदय
16	Dalip Singh	Deoli	Dalip
17	Subodh Kumar	Deoli	Subodh
18	उद्यान	Deoli	उद्यान

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
19	बाबुलाल मीरा	बिना	Babulal
20	रामेश्वर सिंह	जयपुर	Rameshwar
21	रामसिंह	देवली (बान्दली)	Ramsingh
22	पिण्डू सिंह	जयपुर	Pindoo
23	पूरण सिंह	होडा राय सिंह	Puran Singh
24	रामरतन	मिश्रान पुरा	Ramratn
25	चैन सिंह	टोक	Chainsingh
26	लक्ष्मण गुर्जर	मारु	Laxman
27	मनराज दाकड़	मनराज पुरा	Manraj
28	रामराज गुर्जर	टोपा कावावी	Ramraj
29	रामसिंह गुर्जर	होडाराय सिंह	Ramsingh
30	राजू राणा	टोक	Raju
31	रामलेश गुर्जर	होडाराय सिंह	Ramlesh
32	सुरेंद्र गुर्जर	होडाराय सिंह	Surender
33	मोम प्रकाश सेन	होडाराय सिंह	Momprakash
34	आशाराम सेन	होडाराय सिंह	Asharam
35	दलीप पांडे	होडाराय सिंह	Dalip
36	नयन शोर		
37	रामलाल	होडाराय सिंह	Ramlal
38	मनराज गुर्जर - होडा	होडा राय सिंह	Manraj
39	विभाकर गुर्जर	होडाराय सिंह	Vibhakar
40	हिनय गुर्जर	होडाराय सिंह	Hinay
41	चंद्रकांत शर्मा	बोडूवा	Chandrakant
42	क. देवा लाल	बोडूवा	K. Deva Lal
43	शैलान सिंह मीरा	अरासिया	Shailan
44	उनालाल गुर्जर	गोलेवा	Unalal

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
45	विश्वनाथ	कुरुक्षेत्र	विश्वनाथ
46	गोपालराज	बोहरा	गोपालराज
47	मोहनलाल	बोहरा	मोहनलाल
48	मोहनलाल	बोहरा	मोहनलाल
49	विनायक	बोहरा	विनायक
50	लखन चौधरी	बोहरा	लखन चौधरी
51	सोमराज	बोहरा	सोमराज
52	मोहनलाल	बोहरा	मोहनलाल
53	श्रीराम	बोहरा	श्रीराम
54	गोपालराज	बोहरा	गोपालराज
55	विनायक	बोहरा	विनायक
56	विनायक	बोहरा	विनायक
57	विनायक	बोहरा	विनायक
58	विनायक	बोहरा	विनायक
59	सोमराज	बोहरा	सोमराज
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

JEECPJ
26/5/25

संख्या-16-54

1

Dated: 22.05.2025

The Chairperson Madam,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur - chairperson@rpcb.nic.in

The Chairman Sir,
SEIAA, Jaipur - seiaachairman@gmail.com

The Member Secretary Sir,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur- member-secretary@rpcb.nic.in

The Collector Sir,
Tonk - dm-tonk-rj@nic.in

Shri Shiv Kumar Ji, Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Bundi - rorpcb.bundi@gmail.com

Sub: Objections in public hearing scheduled for 26.05.2025 regarding grant of Environmental Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM).

Ref: Public Hearing notice issued by Regional Officer, RSPCB, Bundi bearing No. RPCB/RO.BUNDI/PUB-134/261 dated 07.05.2025 and published in the newspapers.

Dear Sir,

Please refer to public hearing notice cited above, wherein the public hearing is scheduled to be held on 26.05.2025 in respect of enhancement of production in Environmental Clearance from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM). I would like to inform that the terms & conditions containing in the original EC dated 21.08.2024 have not been complied with by the Project Proponent (PP) thereby no occasion arises for consideration of enhancement of production. The pertinent violation of the terms & conditions of EC as well as various guidelines are furnished as under:

1. Under the statutory compliances, the condition has been imposed in the EC at Sl. No. 1.1 that the Environmental Clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and other Court of Law, from time to time, and as applicable to the Project. It is pertinent to mention that the PP is not complying with the orders of Hon'ble Supreme Court of India, which is gross violation of condition



श्री शिव कुमार

imposed under the EC. The brief facts regarding non-compliance to the orders of Hon'ble Supreme Court of India is furnished as under:

- (a) Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 19.02.2020 passed in SLP (C) No. 10587/2019 directed the Central Empowered Committee (CEC) to go into the question of illegal Sand Mining and problems faced in this regard by the various Stakeholders and to suggest measures for stopping illegal mining in the State of Rajasthan.
- (b) The CEC submitted its report dated 23.12.2020 before Hon'ble Supreme Court, wherein under Para-11 (iii), the CEC suggested procedure in respect of River Sand Mining in the State of Rajasthan. Further, under Para-12, in recommendation "D", it is prescribed that *"D. River Sand Mining in Rajasthan is permitted to be conducted after obtaining all statutory clearances and payment of dues and applicable taxes following the procedure listed in Para-11 (iii) of this report"*.
- (c) Hon'ble Supreme Court vide judgment dated 11.11.2021 passed in SLP (C) No. 10587/2019 approved the recommendations made by CEC for implementation forthwith except recommendation "J". Thus, the recommendation 'D' was approved by the Hon'ble Supreme Court and it is the statutory liability of not only the State Government but also the Environmental Department to comply with the conditions laid down under Para 11(iii) of the CEC Report. Further, the compliance of said Para has also been mandated under the Lease Agreement.
- (d) The PP is not complying with the following conditions of Para 11(iii):
 - (a) *The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*
 - (b) *During the course of mining 1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules.*
 - (d) *No mining will be permitted below the river water level.*

21/12

(e) Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/beds exposed above water level.

(f) No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease.

(g) The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities;

(h) The result of replenishment study will be used by the state authorities to update the District Survey Report and to fix the annual permissible limit in respect of such blocks in future.

(l) The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot. This would entail the following:

(ii) The transit depot shall be opened by the lease holder only at sites / locations approved by the DMG;

(iii) The maximum number of transit depots in respect of each lease at any given point of time shall not be more than three.

(iv) The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%.

(v) Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot.

(vi) The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional.

(vii) For transport of sand, royalty paid e-ravannas only shall be used and the e-ravannas shall not be generated for quantity of sand less than the load carrying capacity of the vehicle so used and as certified by the RTO in the vehicles registration document.

21/2/21

(viii) All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority.

(ix) No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot.

(x) All the mining operations are integrated and monitored through digital applications system.

- (e) The aforesaid conditions imposed by the CEC and duly approved by Hon'ble Supreme Court of India and duly highlighted hereinabove are not being followed by PP and the same may be inspected and examined thoroughly before proceeding further regarding grant of EC. It is relevant to mention that (i) there are no linear annual blocks having equal quantity of sand resources (ii) There is no demarcation of Mining Area as laid down by EAC. (iii) The provision for mining in middle 1/3 width is not being followed (iv) The compliance regarding collection of sand from dry sand bars/beds exposed above water level is not being followed (v) No Replenishment Study for the year 2023 and 2024 is on record, which is otherwise mandatory (vi) The provision as mentioned under Para 11(iii) (l) from Sub Para (ii) to (ix) duly highlighted hereinabove are not being complied with by the PP.
- (f) In the light of gross violation of orders of Hon'ble Supreme Court of India, as mentioned above, EC cannot be granted to the PP.

2. There is also violation of various other terms & conditions of EC dated 21.08.2024, which is mentioned in brief as under:

- (a) Under the EC there is provision that approx. 16.845 hectare area will be developed for plantation with 6750 plants. However, there is no any such plantation thereby the same needs to be verified and checked.
- (b) Under Para-3 of Specific Conditions, the condition 1 prescribed that PP is required to carry out Replenishment Study on regular basis as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SMMG) and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM). Further, it is prescribed that PP will ensure Mining operation after incorporation of approved Replenishment Study in Mining Plan. It is relevant to mention that no Replenishment Study has been carried out during 2023 and 2024 thereby the proposal for enhancement of production is bad in law and against the terms & conditions of the EC.

[Handwritten signature]

(c) It is the condition of EC that "The Project Proponent shall comply with all the conditions prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020". However, there is violation of following directions of SSMMG and EMGSM:

- (i) There is non-compliance of the standard environmental conditions for Sand Mining as prescribed under SSMMG (see Page 73), which are at Sl. No. 11 pertaining to Replenishment Study, at Sl. No. 20 & 21 pertaining to Mining Area identification and marking of boundary with pucca pillars and Geo-coordinates, at Sl. No. 31 for transportation of minerals under covered Trucks.
- (ii) Similarly, no any Annual Audit of Sand Mining process, production and compliance of imposed conditions by the Regulatory Authority (Environmental Clearance and Mine Plan) has been carried out in the instant case, which is otherwise mandatory before consideration of the instant proposal, as mandated under Para 4.2 of EMGSM.
- (iii) Further, no Environment Audit, as mandated under Para 6.3 of EMGSM has been carried out, which is mandatory requirement before proceeding further in the instant proposal. The dispatch routes have not been defined as per Para 9.4 (11) of EMGSM.

3. There is no any compliance to the following conditions of EC dated 21.08.2024:

XXXIII. In the project related to Bajri mining the **PP shall follow the 'Sustainable Sand Mining Guidelines 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020' laid down by the MoEF&CC, GOI.** The Bajri sand mining activity is restricted to three meters from ground level or water level whichever is less and the PP shall carry out river sand (Bajri) mining activity only manually or semi mechanized method as provided under the 'Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020'.

2. Air quality monitoring and preservation:

- i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PMI 0, PM2.5, No. 2; CO and SO2 etc as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No.

21/08/24

B-29016/20/90/PCI/I dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. **The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.**

3. Water quality monitoring and preservation:

iii. Project Proponent shall regularly monitor and **maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department/State Pollution Control Board.**

7. Transportation:

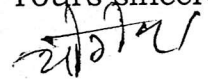
i. **No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with changes of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP** in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

4. The aforesaid conditions of the EC duly highlighted have not been complied with by the PP, which can be verified by physical inspection & records available with the Departments concerned.

Signature

In the light of aforesaid facts duly verifiable on record, it is explicitly clear that on account of gross violation of various terms & conditions of the EC, directions of Hon'ble Supreme Court of India and SSMMG & EMGSM, the present EC granted to M/s Chandak Associates should be revoked immediately and no any proposal for further enhancement of production shall be considered else the Applicant will be left with no option but to proceed further under the provisions of law.

Yours sincerely,



(Yogesh Kumar)

303, Sufal Apartment,
Sawai Jai Singh Highway,
Bani Park, Jaipur (Rajasthan)

JEECP)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:—/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19137

दिनांक 20/05/2025

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी



विषय:— मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर ने मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है।

अतः श्री योगेश कुमार, सवाई जयसिंह हाईवे बनी पार्क जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न क्रमांक 7

(विनोद कुमार मीणा)
प्रभारी अधिकारी
न्याय अनुभाग कलेक्टर,
टोंक

Dated: 22.05.2025

The Chairperson Madam,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur - chairperson@rpcb.nic.in

The Chairman Sir,
SEIAA, Jaipur - seiaachairman@gmail.com

The Member Secretary Sir,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur - member-secretary@rpcb.nic.in

The Collector Sir,
Tonk - dm-ton-rj@nic.in

Shri Shiv Kumar Ji, Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Bundi - rorpcb.bundi@gmail.com

Sub: Objections in public hearing scheduled for 26.05.2025 regarding grant of Environmental Clearance (EC) for proposed enhancement of production from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM).

Ref: Public Hearing notice issued by Regional Officer, RSPCB, Bundi bearing No. RPCB/RO BUNDI/PUB-134/261 dated 07.05.2025 and published in the newspapers.

Dear Sir,

Please refer to public hearing notice cited above, wherein the public hearing is scheduled to be held on 26.05.2025 in respect of enhancement of production in Environmental Clearance from 3.0 million TPA (ROM) to 8.2 million TPA (ROM). I would like to inform that the terms & conditions containing in the original EC dated 21.08.2024 have not been complied with by the Project Proponent (PP) thereby no occasion arises for consideration of enhancement of production. The pertinent violation of the terms & conditions of EC as well as various guidelines are furnished as under:

1. Under the statutory compliances, the condition has been imposed in the EC at Sl. No. 1.1 that the Environmental Clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and other Court of Law, from time to time, and as applicable to the Project. It is pertinent to mention that the PP is not complying with the orders of Hon'ble Supreme Court of India, which is gross violation of condition

21/5/25

imposed under the EC. The brief facts regarding non-compliance to the orders of Hon'ble Supreme Court of India is furnished as under:

- (a) Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 19.02.2020 passed in SLP (C) No. 10587/2019 directed the Central Empowered Committee (CEC) to go into the question of illegal Sand Mining and problems faced in this regard by the various Stakeholders and to suggest measures for stopping illegal mining in the State of Rajasthan.
- (b) The CEC submitted its report dated 23.12.2020 before Hon'ble Supreme Court, wherein under Para-11 (iii), the CEC suggested procedure in respect of River Sand Mining in the State of Rajasthan. Further, under Para-12, in recommendation "D", it is prescribed that *"D. River Sand Mining in Rajasthan is permitted to be conducted after obtaining all statutory clearances and payment of dues and applicable taxes following the procedure listed in Para-11 (iii) of this report"*.
- (c) Hon'ble Supreme Court vide judgment dated 11.11.2021 passed in SLP (C) No. 10587/2019 approved the recommendations made by CEC for implementation forthwith except recommendation 'J'. Thus, the recommendation 'D' was approved by the Hon'ble Supreme Court and it is the statutory liability of not only the State Government but also the Environmental Department to comply with the conditions laid down under Para 11(iii) of the CEC Report. Further, the compliance of said Para has also been mandated under the Lease Agreement.
- (d) The PP is not complying with the following conditions of Para 11(iii):
 - (a) *The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*
 - (b) *During the course of mining 1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules.*
 - (d) *No mining will be permitted below the river water level.*

21/12/21

- (e) Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/beds exposed above water level.
- (f) No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease.
- (g) The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities;
- (h) The result of replenishment study will be used by the state authorities to update the District Survey Report and to fix the annual permissible limit in respect of such blocks in future.
- (i) The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot. This would entail the following:
- (ii) The transit depot shall be opened by the lease holder only at sites / locations approved by the DMG;
 - (iii) The maximum number of transit depots in respect of each lease at any given point of time shall not be more than three.
 - (iv) The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%.
 - (v) Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot.
 - (vi) The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional.
 - (vii) For transport of sand, royalty paid e-ravannas only shall be used and the e-ravannas shall not be generated for quantity of sand less than the load carrying capacity of the vehicle so used and as certified by the RTO in the vehicles registration document.

21/07/

(viii) All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority.

(ix) No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot.

(x) All the mining operations are integrated and monitored through digital applications system.

- (e) The aforesaid conditions imposed by the CEC and duly approved by Hon'ble Supreme Court of India and duly highlighted hereinabove are not being followed by PP and the same may be inspected and examined thoroughly before proceeding further regarding grant of EC. It is relevant to mention that (i) there are no linear annual blocks having equal quantity of sand resources (ii) There is no demarcation of Mining Area as laid down by EAC. (iii) The provision for mining in middle 1/3 width is not being followed (iv) The compliance regarding collection of sand from dry sand bars/beds exposed above water level is not being followed (v) No Replenishment Study for the year 2023 and 2024 is on record, which is otherwise mandatory (vi) The provision as mentioned under Para 11(iii) (l) from Sub Para (ii) to (ix) duly highlighted hereinabove are not being complied with by the PP.
- (f) In the light of gross violation of orders of Hon'ble Supreme Court of India, as mentioned above, EC cannot be granted to the PP.

2. There is also violation of various other terms & conditions of EC dated 21.08.2024, which is mentioned in brief as under:

- (a) Under the EC there is provision that approx. 16.845 hectare area will be developed for plantation with 6750 plants. However, there is no any such plantation thereby the same needs to be verified and checked.
- (b) Under Para-3 of Specific Conditions, the condition 1 prescribed that PP is required to carry out Replenishment Study on regular basis as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SMMG) and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM). Further, it is prescribed that PP will ensure Mining operation after incorporation of approved Replenishment Study in Mining Plan. It is relevant to mention that no Replenishment Study has been carried out during 2023 and 2024 thereby the proposal for enhancement of production is bad in law and against the terms & conditions of the EC.

21/08/24

(c) It is the condition of EC that "The Project Proponent shall comply with all the conditions prescribed in Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020". However, there is violation of following directions of SSMMG and EMGSM:

- (i) There is non-compliance of the standard environmental conditions for Sand Mining as prescribed under SSMMG (see Page 73), which are at Sl. No. 11 pertaining to Replenishment Study, at Sl. No. 20 & 21 pertaining to Mining Area identification and marking of boundary with pucca pillars and Geo-coordinates, at Sl. No. 31 for transportation of minerals under covered Trucks.
- (ii) Similarly, no any Annual Audit of Sand Mining process, production and compliance of imposed conditions by the Regulatory Authority (Environmental Clearance and Mine Plan) has been carried out in the instant case, which is otherwise mandatory before consideration of the instant proposal, as mandated under Para 4.2 of EMGSM.
- (iii) Further, no Environment Audit, as mandated under Para 6.3 of EMGSM has been carried out, which is mandatory requirement before proceeding further in the instant proposal. The dispatch routes have not been defined as per Para 9.4 (11) of EMGSM.

3. There is no any compliance to the following conditions of EC dated 21.08.2024:

XXXIII. In the project related to Bajri mining the **PP shall follow the 'Sustainable Sand Mining Guidelines 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020' laid down by the MoEF&CC, GOI.** The Bajri sand mining activity is restricted to three meters from ground level or water level whichever is less and the PP shall carry out river sand (Bajri) mining activity only manually or semi mechanized method as provided under the 'Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016' and 'Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020'.

2. Air quality monitoring and preservation:

- i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO₂; CO and SO₂ etc as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No.

21/08/24

B-29016/20/90/PCI/I dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. **The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.**

3. Water quality monitoring and preservation:

iii. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department/State Pollution Control Board.

7. Transportation:

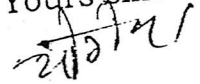
i. **No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations.** In such cases, **PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters)** so that the adverse impact of sound and dust along with changes of accidents could be mitigated. **All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP** in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

4. The aforesaid conditions of the EC duly highlighted have not been complied with by the PP, which can be verified by physical inspection & records available with the Departments concerned.

Signature

In the light of aforesaid facts duly verifiable on record, it is explicitly clear that on account of gross violation of various terms & conditions of the EC, directions of Hon'ble Supreme Court of India and SSMMG & EMGSM, the present EC granted to M/s Chandak .Associates should be revoked immediately and no any proposal for further enhancement of production shall be considered else the Applicant will be left with no option but to proceed further under the provisions of law.

Yours sincerely,



(Yogesh Kumar)
303, Sufal Apartment,
Sawai Jai Singh Highway,
Bani Park, Jaipur (Rajasthan)

JEE (P)

26/5/25

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक (राजस्थान)

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
क्षेत्रीय कार्यालय बूंदी (राजस्थान)

विषय: मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में बजरी खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में बजरी खनन की मात्रा 3 लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2025 को जनसुनवाई क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा नियत की गयी है।

इस पर्यावरण स्वीकृति का हम स्थानीय निवासी घोर विरोध करते हैं। यदि नदी से प्रतिवर्ष इतनी बजरी निकाली जायेगी, तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से नदी को हानि होगी, अपितु स्थानीय जल स्तर में भी कमी होगी।

यह सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की कोई पालना नहीं की गयी है तथा उसकी जाँच किये बिना मात्रा में वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया जाना घोर निन्दनीय है। मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को जारी ई. सी. एवं सी.टी.ओ. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शर्त रखी गयी है, जिसमें लीज में उल्लेखित यह शर्त भी है कि लीजधारक द्वारा सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के निर्देशों की पालना की जायेगी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11.2021 से अनुमोदित किया गया है।

प्राप्त



सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के अन्तर्गत यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि लीज क्षेत्र को समान 05 लिनियर ब्लॉक में विभाजित करना है तथा यह ब्लॉक इस हिसाब से बनाना है कि सभी ब्लॉक में लगभग समान-समान रूप से बजरी की मात्रा उपलब्ध हो। इसके साथ ही हर वर्ष केवल एक ब्लॉक में ही खनन का कार्य किया जाना है, जिसमें नदी के दोनों ओर के 1/3 भाग न्यूनतम दूरी को छोड़ते हुए ही खनन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल लीज क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग के न्यूनतम दूरी को छोड़ने के उपरान्त अवशेष 1/3 भाग अर्थात् लगभग 6.6 प्रतिशत लीज भाग में ही प्रतिवर्ष बजरी का संकलन किये जाने की अनुमति है। विभाग द्वारा बिना इसका अध्ययन कराये कि प्रतिवर्ष अनुमत किये गये 6.6 प्रतिशत भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी उपलब्ध भी है या नहीं, किस प्रकार इस प्रस्ताव को जनसुनवाई के लिए लाया गया है। न तो विभाग द्वारा एवं न ही सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा इस अध्ययन का कोई दस्तावेज पर्यावरण के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा पर्यावरण के पोर्टल पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार 05 लिनियर ब्लॉक बनाये गये हैं तथा किस ब्लॉक में किस वर्ष बजरी संकलन की जायेगी एवं उस ब्लॉक के नदी के मध्य हेतु अनुमति प्राप्त 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी भी उपलब्ध है या नहीं।

इस प्रकार विभाग द्वारा यह प्रस्ताव केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए जनसुनवाई हेतु रखा गया है, जबकि विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी के निर्देशों की जानकारी होना एवं उन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना चाहिए था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं के अनुसार निम्न प्रावधानों की पालना अनिवार्य है:

जय

- समस्त लीज क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित करके सीमांकन किया जाना है तथा प्रतिवर्ष केवल एक भाग में ही खनन कार्य किया जा सकता है तथा 05 वर्ष की लीज अवधि में उस भाग में पुनः खनन नहीं किया जा सकता है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (a) *The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*

सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (f) *No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease).*
- खनन में नदी के दोनों क्षेत्र के 1/3 भाग को छोड़कर अवशेष 1/3 भाग में ही बजरी खनन किया जा सकता है, जो 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (b) *During the course of mining 1/3 width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining 1/3 width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules).*
- नदी के जल स्तर से नीचे खनन की अनुमति नहीं है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (d) *No mining will be permitted below the river water level).*
- बजरी केवल सूखे बजरी के ढेर अथवा जल स्तर के ऊपर ही निकाली जा सकती है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (e) *Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/ beds exposed above water level).*

जम

- प्रत्येक मानसून के सीजन में वार्षिक रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी करनी है। रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के आधार पर ही वार्षिक बजरी खनन की सीमा का निर्धारण किया जाना है। रिप्लेनिशमेन्ट की मात्रा से अधिक बजरी के खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (g) *The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities*).
- लीज धारक द्वारा नदी क्षेत्र से बजरी का विक्रय नहीं किया जा सकता है। लीजधारक द्वारा बजरी को खनन कर ट्रांजिट डिपो में लाना है तथा ट्रांजिट डिपो में अनलोड करके ही बजरी का विक्रय किया जा सकता है। ट्रांजिट डिपो हेतु समुचित अनुमति प्राप्त करनी है, जो सम्पूर्ण लीज क्षेत्र हेतु 3 से अधिक नहीं हो सकती है।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) *The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot*).
- नदी क्षेत्र में खनन के उपरान्त बजरी को मोबाईल वे-ब्रिज से तौलना है तथा ट्रांजिट डिपो में पुनः तौलकर अनलोड करना है तथा दोनों के वजन में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (iv) *The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%*).
- केवल जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. टैग वाले वाहन ही नदी से ट्रांजिट डिपो में बजरी का परिवहन कर सकते हैं।

514

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (v) *Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot).*

- ट्रांजिट डिपो में 24x7 सी.सी.टी.वी. कवरेज अनिवार्य है, जिसका डाटा 6 महीने का संघारण किया जाना है। यदि सी.सी.टी.वी. कार्यरत नहीं है तो ट्रांजिट डिपो से बजरी की प्राप्ति एवं बजरी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (vi) *The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional).*

- वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक बजरी का परिवहन नहीं किया जा सकता है।

- सभी ई-रवन्ना एवं ट्रांजिट पास भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित एम. आई.सी.आर. पेपर पर ही छपे होने चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील से जारी करना होगा।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (viii) *All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority).*

- जो ट्रैक्टर वाणिज्यिक रूप में पंजीकृत नहीं है, उनसे खनिज क्षेत्र से ट्रांजिट डिपो हेतु बजरी परिवहन नहीं किया जा सकता है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (ix) *No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot).*

उक्त नियमों एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति तथा विभिन्न वैधानिक नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि बजरी खनन नदी में ग्राउण्ड लेवल से 01 मीटर अथवा वाटर लेवल, जो भी कम हो उसी पर किया जा सकता है, जिसे ग्राउण्ड लेवल से 03 मीटर की अनुमति से पूर्व

जध

वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में खननकर्ता द्वारा वाटर लेवल से नीचे भी खनन कार्य किया गया है तथा कई स्थानों पर किये गये गड्ढों की नाप से यह स्पष्ट होगा कि ग्राउण्ड लेवल से 01/03 मीटर तथा वाटर लेवल के नियमों की पालना नहीं की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जारी पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करने योग्य है।

वैधानिक प्रावधानों एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों में प्रतिवर्ष रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी कराये जाने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो उचित नहीं है। यहाँ तक कि वैधानिक प्रावधानों में पर्यावरण स्वीकृति में बजरी परिवहन हेतु रूट निर्धारित करने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी पर्यावरण स्वीकृति में इसका न तो उल्लेख किया गया है एवं न ही ऐसा कोई रूट पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा बिना उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित किये मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को ई.सी. की मात्रा में तीन लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन की वृद्धि हेतु ई.सी. प्रस्तावित की गयी है, जो पूर्णतया अवैध एवं अस्वीकार्य है। विभाग द्वारा न तो यह सुनिश्चित किया गया है कि बजरी के वर्ष 2023 एवं 2024 में किये गये रिप्लेनिशमेन्ट अध्ययन के उपरान्त प्रत्येक लिनियर ब्लॉक के मध्य स्थित 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन का रिप्लेनिशमेन्ट हुआ है अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष हेतु अनुमत भाग में इस मात्रा का रिप्लेनिशमेन्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना रिप्लेनिशमेन्ट का अधिकृत संस्थान से अध्ययन कराये बिना किसी प्रकार की कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है।

यह अत्यधिक खेदजनक है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में खननकर्ता को 6,750 पेड़ लगाने थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है कि उक्त खननकर्ता द्वारा कोई पौधारोपण नहीं किया गया है, विभाग द्वारा इसकी पालना करवाने के बाद ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त एयर क्वालिटी तथा वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग की शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है।

खननकर्ता को जारी पर्यावरण स्वीकृति में बाई-पास रोड़ बनाने एवं गाँव के रोड़ से ट्रकों का परिवहन नहीं करने के प्रावधान होने के बाद भी खननकर्ता द्वारा बाई-पास रोड़ नहीं बनाये गये हैं तथा गाँवों के रोड़ से बजरी के ट्रकों के निकलने के कारण सारे रोड़ खराब

जय

हो गये हैं, जबकि रोड़ की चौड़ाई एवं क्षमता बढ़ाने का दायित्व खननकर्ता का है, लेकिन खननकर्ता द्वारा बिना रोड़ बनाये बजरी के ट्रक भरे जा रहे हैं, जो पूर्णतया अवैध है।

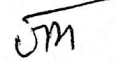
ऐसी स्थिति में उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है तथा स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरण के विपरीत काम करने वाले खननकर्ता को जारी ई.सी. तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अविलम्ब निरस्त किया जाये, ताकि क्षेत्र के पर्यावरण की समुचित रक्षा हो सके।

दिनांक: 24.05.2025

स्थान: टोडारायसिंह (टोंक)

भवदीय



(जय सिंह नरुका)

निवासी ग्राम खरेड़ा, तहसील टोडारायसिंह,
जिला टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 13092 दिनांक 26/05/2025

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी

JEE (P) / P^m
02/06/25

विषय:- मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में श्री जयसिंह नरुका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री जयसिंह नरुका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ने मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है।

अतः श्री जयसिंह नरुका निवासी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न किता - 7



(विनोद कुमार मीणा)
प्रभारी अधिकारी
न्याय अनुभाग कलेक्टर,
टोंक

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक (राजस्थान)

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, —
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
क्षेत्रीय कार्यालय बूंदी (राजस्थान)

विषय: मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा वांछित पर्यावरण स्वीकृति वास्ते बजरी खनन तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स द्वारा तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में बजरी खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में बजरी खनन की मात्रा 3 लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2025 को जनसुनवाई क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा नियत की गयी है।

इस पर्यावरण स्वीकृति का हम स्थानीय निवासी घोर विरोध करते हैं। यदि नदी से प्रतिवर्ष इतनी बजरी निकाली जायेगी, तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से नदी को हानि होगी, अपितु स्थानीय जल स्तर में भी कमी होगी।

यह सुस्पष्ट है कि सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की कोई पालना नहीं की गयी है तथा उसकी जाँच किये बिना मात्रा में वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया जाना घोर निन्दनीय है। मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को जारी ई. सी. एवं सी.टी.ओ. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शर्त रखी गयी है, जिसमें लीज में उल्लेखित यह शर्त भी है कि लीजधारक द्वारा सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के निर्देशों की पालना की जायेगी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11.2021 से अनुमोदित किया गया है।

जाम

सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के अन्तर्गत यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि लीज क्षेत्र को समान 05 लिनियर ब्लॉक में विभाजित करना है तथा यह ब्लॉक इस हिसाब से बनाना है कि सभी ब्लॉक में लगभग समान-समान रूप से बजरी की मात्रा उपलब्ध हो। इसके साथ ही हर वर्ष केवल एक ब्लॉक में ही खनन का कार्य किया जाना है, जिसमें नदी के दोनों ओर के 1/3 भाग न्यूनतम दूरी को छोड़ते हुए ही खनन किया जा सकता है। इस प्रकार कुल लीज क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग के न्यूनतम दूरी को छोड़ने के उपरान्त अवशेष 1/3 भाग अर्थात् लगभग 6.6 प्रतिशत लीज भाग में ही प्रतिवर्ष बजरी का संकलन किये जाने की अनुमति है। विभाग द्वारा बिना इसका अध्ययन कराये कि प्रतिवर्ष अनुमत किये गये 6.6 प्रतिशत भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी उपलब्ध भी है, या नहीं, किस प्रकार इस प्रस्ताव को जनसुनवाई के लिए लाया गया है। न तो विभाग द्वारा एवं न ही सम्बन्धित खननकर्ता द्वारा इस अध्ययन का कोई दस्तावेज पर्यावरण के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा पर्यावरण के पोर्टल पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार 05 लिनियर ब्लॉक बनाये गये हैं तथा किस ब्लॉक में किस वर्ष बजरी संकलन की जायेगी एवं उस ब्लॉक के नदी के मध्य हेतु अनुमति प्राप्त 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन बजरी भी उपलब्ध है या नहीं।

इस प्रकार विभाग द्वारा यह प्रस्ताव केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए जनसुनवाई हेतु रखा गया है, जबकि विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी के निर्देशों की जानकारी होना एवं उन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना चाहिए था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं के अनुसार निम्न प्रावधानों की पालना अनिवार्य है:

जम

- समस्त लीज क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित करके सीमांकन किया जाना है तथा प्रतिवर्ष केवल एक भाग में ही खनन कार्य किया जा सकता है तथा 05 वर्ष की लीज अवधि में उस भाग में पुनः खनन नहीं किया जा सकता है।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (a) *The entire lease area along the river is divided into five linear annual blocks having nearly equal quantity of sand resource for annual extraction during the 5 year period of lease. The boundaries of the river to be leased for sand mining are to be demarcated after following the procedure laid down by the EAC in its meeting held on 8th Jan, 2018. An extract of the minutes 87 dated 8.1.2018 is enclosed as Annexure R 21 to this Report.*
सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (f) *No sand will be collected from any of the annual blocks from where sand has already been mined during any of the 5 year period of the lease).*
- खनन में नदी के दोनों क्षेत्र के $1/3$ भाग को छोड़कर अवशेष $1/3$ भाग में ही बजरी खनन किया जा सकता है, जो 7.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (b) *During the course of mining $1/3$ width of the river in central part will be dugout all along the length of the annual block without any gap to maintain continuity of channel and the depth of mining will be maintained at uniform 1 M until the replenishment study is undertaken. The remaining $1/3$ width of the river on either side of the river shall not be less than 7.5 M each and which is the minimum width of safety zone prescribed in the Mining Rules).*
- नदी के जल स्तर से नीचे खनन की अनुमति नहीं है।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (d) *No mining will be permitted below the river water level).*
- बजरी केवल सूखे बजरी के ढेर अथवा जल स्तर के ऊपर ही निकाली जा सकती है।
(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (e) *Sand is permitted to be collected only from dry sand bars/beds exposed above water level).*

जम

- प्रत्येक मानसून के सीजन में वार्षिक रिप्लेनिशमेंट स्टडी करनी है। रिप्लेनिशमेंट स्टडी के आधार पर ही वार्षिक बजरी खनन की सीमा का निर्धारण किया जाना है। रिप्लेनिशमेंट की मात्रा से अधिक बजरी के खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (g) *The lease condition shall include mandating the lessee to undertake annual replenishment studies over the entire period of the lease during the monsoon season in respect of each of the annual blocks already mined by the lessee and make available the same to the state authorities.*)

- लीज धारक द्वारा नदी क्षेत्र से बजरी का विक्रय नहीं किया जा सकता है। लीजधारक द्वारा बजरी को खनन कर ट्रांजिट डिपो में लाना है तथा ट्रांजिट डिपो में अनलोड करके ही बजरी का विक्रय किया जा सकता है। ट्रांजिट डिपो हेतु समुचित अनुमति प्राप्त करनी है, जो सम्पूर्ण लीज क्षेत्र हेतु 3 से अधिक नहीं हो सकती है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) *The lessees shall not sell and despatch the mined sand directly from the river bed to customer destinations. Instead the lessee shall first transport mined sand to the designated transit depot to be maintained within 5 kms radial distance from the river bank and sell and despatch sand to customer destinations only from the transit depot.*)

- नदी क्षेत्र में खनन के उपरान्त बजरी को मोबाइल वे-ब्रिज से तौलना है तथा ट्रांजिट डिपो में पुनः तौलकर अनलोड करना है तथा दोनों के वजन में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (iv) *The river sand shall be weighed at mining site using mobile weigh bridge before its dispatch to the transit depot and a second weighment shall be taken at the transit depot gate before the same is unloaded. The difference in two weighments shall not exceed 5%.*)

- केवल जी.पी.एस. एवं आर.एफ.आई.डी. टैग वाले वाहन ही नदी से ट्रांजिट डिपो में बजरी का परिवहन कर सकते हैं।

5/14

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (v) *Only GPS (Global Positioning System) fitted vehicles with RFID Tag (Radio Frequency Identification Device) are engaged in transport of sand from the mining site to the transit depot).*

- ट्रांजिट डिपो में 24x7 सी.सी.टी.वी. कवरेज अनिवार्य है, जिसका डाटा 6 महीने का संघारण किया जाना है। यदि सी.सी.टी.वी. कार्यरत नहीं है तो ट्रांजिट डिपो से बजरी की प्राप्ति एवं बजरी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (vi) *The entire area of transit depot including the gate and weigh bridge shall be brought under 24X7 CCTV coverage and CCTV data/recordings shall be maintained for six months. No dispatch or receipt of sand in the transit depot shall be made if the CCTV system for any reason is not functional).*

- वाहन की स्वीकृत क्षमता से अधिक बजरी का परिवहन नहीं किया जा सकता है।
- सभी ई-रवन्ना एवं ट्रांजिट पास भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित एम. आई.सी.आर. पेपर पर ही छपे होने चाहिए जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं सील से जारी करना होगा।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (viii) *All transit passes (e-ravannas) are printed on Indian Bank Association approved Magnetic Ink Character Recognition code (MICR) paper. These papers shall be supplied by the State government with the seal and signature of the issuing authority).*

- जो ट्रैक्टर वाणिज्यिक रूप में पंजीकृत नहीं है, उनसे खनिज क्षेत्र से ट्रांजिट डिपो हेतु बजरी परिवहन नहीं किया जा सकता है।

(सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा 11(iii) का उप पैरा (l) (ix) *No tractor, not being registered as commercial vehicles, shall be engaged for transport of sand from the mining site to the transit depot).*

उक्त नियमों एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति तथा विभिन्न वैधानिक नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि बजरी खनन नदी में ग्राउण्ड लेवल से 01 मीटर अथवा वाटर लेवल, जो भी कम हो उसी पर किया जा सकता है, जिसे ग्राउण्ड लेवल से 03 मीटर की अनुमति से पूर्व

जम

वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में खननकर्ता द्वारा वाटर लेवल से नीचे भी खनन कार्य किया गया है तथा कई स्थानों पर किये गये गड्ढों की नाप से यह स्पष्ट होगा कि ग्राउण्ड लेवल से 01/03 मीटर तथा वाटर लेवल के निम्नो की पालना नहीं की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जारी पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करने योग्य है।

वैधानिक प्रावधानों एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों में प्रतिवर्ष रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी कराये जाने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है, जो उचित नहीं है। यहाँ तक कि वैधानिक प्रावधानों में पर्यावरण स्वीकृति में बजरी परिवहन हेतु रूट निर्धारित करने का अनिवार्य प्रावधान होने के उपरान्त भी पर्यावरण स्वीकृति में इसका न तो उल्लेख किया गया है एवं न ही ऐसा कोई रूट पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा बिना उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित किये मैसर्स चाण्डक एसोसिएट्स को ई.सी. की मात्रा में तीन लाख मै.टन से 8.2 लाख मै.टन की वृद्धि हेतु ई.सी. प्रस्तावित की गयी है, जो पूर्णतया अवैध एवं अस्वीकार्य है। विभाग द्वारा न तो यह सुनिश्चित किया गया है कि बजरी के वर्ष 2023 एवं 2024 में किये गये रिप्लेनिशमेन्ट अध्ययन के उपरान्त प्रत्येक लिनियर ब्लॉक के मध्य स्थित 1/3 भाग में 8.2 लाख मै.टन का रिप्लेनिशमेन्ट हुआ है अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष हेतु अनुमत भाग में इस मात्रा का रिप्लेनिशमेन्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में बिना रिप्लेनिशमेन्ट का अधिकृत संस्थान से अध्ययन कराये बिना किसी प्रकार की कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है।

यह अत्यधिक खेदजनक है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में खननकर्ता को 6,750 पेड़ लगाने थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है कि उक्त खननकर्ता द्वारा कोई पौधारोपण नहीं किया गया है, विभाग द्वारा इसकी पालना करवाने के बाद ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त एयर क्वालिटी तथा वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग की शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है।

खननकर्ता को जारी पर्यावरण स्वीकृति में बाई-पास रोड़ बनाने एवं गाँव के रोड़ से ट्रकों का परिवहन नहीं करने के प्रावधान होने के बाद भी खननकर्ता द्वारा बाई-पास रोड़ नहीं बनाये गये हैं तथा गाँवों के रोड़ से बजरी के ट्रकों के निकलने के कारण सारे रोड़ खराब

ज.प.

हो गये हैं, जबकि रोड़ की चौड़ाई एवं क्षमता बढ़ाने का दायित्व खननकर्ता का है, लेकिन खननकर्ता द्वारा बिना रोड़ बनाये बजरी के ट्रक भरे जा रहे हैं, जो पूर्णतया अवैध है।

ऐसी स्थिति में उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है तथा स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरण के विपरीत काम करने वाले खननकर्ता को जारी ई.सी. तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अविलम्ब निरस्त किया जाये, ताकि क्षेत्र के पर्यावरण की समुचित रक्षा हो सके।

दिनांक: 24.05.2025

स्थान: टोडारायसिंह (टोंक)---

भवदीय



(जय सिंह नरुका)

निवासी ग्राम खरेड़ा, तहसील टोडारायसिंह,
जिला टोंक

सेवामें,

श्रीमान.....
 ४७० ५० १० म. १०० १०० १००

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
 प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नहीं करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नहीं करने से स्पष्ट है कि एसोसिएट्स ने सी.ई. सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डों की खुली अवहेलना है। इस कारण से



लगातार.....2

//2//

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
4. यह कि उक्त एसोसियट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दृष्टि से हरे पेड़ों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सड़को का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

//3//

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़ कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़ कर करना होता है, नहीं कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।
7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रुक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।
8. खनन कार्यो के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है2025..... वर्ष में 3.0, प्रिलेवन सी.ई.सी. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन..... 8.2 प्रिलेवन सी.ई.सी. के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरुद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी की स्वीकृति नहीं दी जाए।

दिनांक :- 26/5/2023

प्रार्थी प्रिलेवन सी.ई.सी.

मनोज कुमार चण्डा
नि. वरकपुर तह- प्रिलेवन सी.ई.सी.
मो. नं. 9929972733

Received in Public Money
JEE (P)

26/5/25

सेवामें,

श्रीमान पु. जय. डा. धिकारी
रीटो डि. वन. सु. ई. (राज.)

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नहीं करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नहीं करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई. सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डों की खुली अवहेलना है। इस कारण से

लगातार.....2



माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्लंघन है।
4. यह कि उक्त एसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दृष्टि से हरे पेड़ों व पौधों को नुकसान पहुँचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सड़को का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्लंघन है।
5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जस्त नहीं किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड

//3//

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड़ कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़ कर करना होता है, नहीं कर रहा है सी.ई.सी का उल्लंघन है।

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रुक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्लंघन है।

8. खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलियन टी.पी. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन 8.2 मिलियन टी.पी. के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरुद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी की स्वीकृति नहीं दी जाए।

दिनांक :- 26/05/2025

प्रार्थी

9982836150

रमेश कुमार शर्मा / रमेश कुमार शर्मा
200 ई.एम.ए. को 200 ई.एम.ए.
के 200 ई.एम.ए. के 200 ई.एम.ए.

सेवामे,

श्रीमान श्री गीत उम्हकरी

21. प्र. वि. म. बुन्दी

JEECP)
26/5/25

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नहीं करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये है जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नहीं करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई. सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डों की खुली अवहलेना है। इस कारण से



//2//

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
4. यह कि उक्त एसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दुष्टि से हरे पेड़ों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सड़को का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़

// 3 //

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड़ कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़ कर करना होता है, नहीं कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।

7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रुक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।

8. खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में

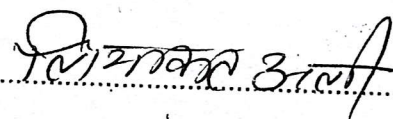
3.0 मिलीमिटर सी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन....

8.2 मिलीमिटर सी.पी.ए. (3.11.20) के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरुद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी की स्वीकृति नहीं दी जाए।

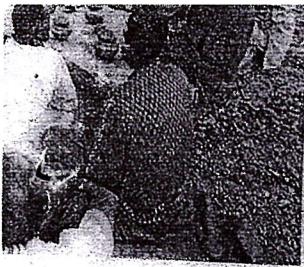
दिनांक :- 26/5/2025


प्रार्थी



स्वतंत्र पत्रकार

M-7014653770



परियों को अंतिम रूप दिया।

पाणिग्रहण संस्कार व रात 9 बजे आशीर्वाद समारोह होगा।

कथा का आयोजन



वाले श्रीराम महायज्ञ की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री जोडला बालाजी बालापुरा मेहरु में 14 से 22 मई तक इक्कीस कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ होगा।

बुधवार को मंदिर परिसर में यज्ञ कर्ता संत याज्ञिक सम्राट श्री श्री 1008 श्री मुनेश्वर दास महाराज

महात्मा गांधी स्कूल में

प्रवेश शुरू 15 जून तक होगा

दूनी महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी से दसवीं तक प्रवेश 15 जून तक लिए जाएंगे।

16 जून को प्राप्त आवेदनों की सूची विद्यालय बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की अंतिम सूची बोर्ड पर लगाई जाएगी। 19 जून से प्रवेश शुरू होगा। 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती चम्पा देवी** (धर्मपत्नी : स्व. श्री गोकुलचन्द जी जैन) का स्वर्गवास दिनांक 07 मई 2025 को हो गया है। जिनकी **तीये की बैठक** 09 मई 2025 शुरुवार को सुबह 9 से 10 बजे तक जैन मन्दिर मेहन्दावास पर रखी गई है।
नोट : यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।

शोकाकुल

महादेव प्रसाद, बाबूलाल, धर्मचन्द, भैरूलाल (देवर), प्रकाशचन्द, डालचन्द, मीठालाल, विमल, किशनचन्द, नूरु, अशोक, परस, पवन कुमार, संजय कुमार (पुत्र), अनिल, अक्षय, रिवम, मरूम (पौत्र), कनिष्क (पौत्र) एक समस्त गर्भ परिवार, अरुनिया नील वाले मेहन्दावास मो. 9950612128, 9929600105
श्रीहर पक्ष : श्रीमान नेमीचन्द जी, धर्मचन्द जी, विनोद कुमार जी, पिन्दू जी टोरडी वाले मालपुरा

आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गईं। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

इस मौके पर मेहरु, बालापुरा खेड़ा मलका नगर वन का खेड़ा, मेहरुवारी की ढाणी, जनकपुरा तिलरिया, रामेश्वरपुरा छोपट की

क गावा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महायज्ञ में काशी, जनकपुर, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा सहित कई आश्रमों से साधु-संत आएंगे। 18 मई को शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। महायज्ञ के दौरान श्रीराम कथा और शाम को रासलीला का आयोजन किया जाएगा।


Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishward Fruit Garden, New Colony, Bundi
 E-mail: rpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO-Bundi/PUB-134/261 Date: 07/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मसं सं. 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.86 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरावा, बनेड़िया धारणान, केदारबास, चन्दपुरा, सालगाबास, गोलाहडा, रलावला, ठाठा, सतीबास, जेधलिया, रामावलीपुरा, मोर भाटिया, मोरडा, मोडियाला, छानमयबासपुरा, बरबास एवं घुली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सैण्ड (साईनर मिनेरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान प्रचायत समिति समारोह, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी आप सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **RPCB/RO-Bundi/PUB-134/2323** दिनांक 26/05/2025 द्वारा जारी कर देनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 01/04/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 01/04/2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2. चूंकि उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आप सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **RPCB/RO-Bundi/PUB-134/2323** दिनांक 03/05/2025 द्वारा जारी कर देनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05/05/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 05/05/2025 को प्रकाशित की गयी।

3. चूंकि, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07/05/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गई है।

4. चूंकि, मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006, संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित आपट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अधिलेख निम्न कार्यालयों में अबलोकनाय उपलब्ध है:-

- कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
- कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
- कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
- प्रचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।
- उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
- क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झुंगरी, जयपुर।
- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, च.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुन्दी, जिला बुन्दी।
- कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07.05.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को स्थान प्रचायत समिति समारोह, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सूचना में लिखित आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुन्दी-जिला बुन्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

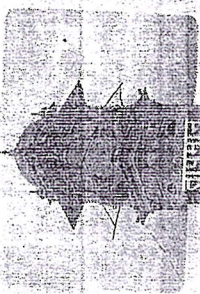
भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी सा.प्रति.म. बुन्दी

CLASSIFIED

BhaskarAd.com
Classified Ad आँतलाइन बुक करें
Call: 9772019222



राष्ट्र भौतन



बिजली

32° अधिकतम
24° न्यूनतम

हमिडिटी 66% (अधिकतम)
हवा की गति 26.0 किमी/घंटा

फारवार्ड

मौसम साफ रहने की संभावना
(सित-मौसम केंद्र टोक)

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

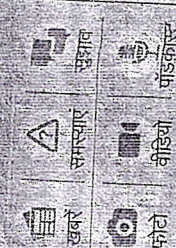
पत्रिका.com

टोक 32 30%

अक्षा	टोक	प्रदेश
0-50	51-100	101-200
201-300	301-400	401-500

रीडर्स कनेक्ट

हमें भेजें



ई-मेल: tonked@patrika.com
वॉट्सएप: 9660439374

पृष्ठ पचास खबरें
दखे फालो/वाडिया

patrika.com/tonk-news
क्यूआर कोड को
मोबाइल से
करें स्कैन



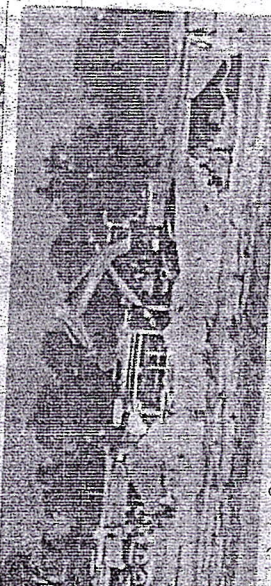
इससे जुड़ें
facebook.com/patrika.tonk

आमनी हलचल

अब तो बरख़्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्म, एनजीटी ने लगाई रोक

टोडारायसिंह क्षेत्र में चल रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्म होने के कारण पर है। ऐसे में तय क्षमता से अधिक खनन नहीं करने पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमानुसार जन्मुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लेगा बैठक



टोक, बनास नदी में बजरी के लिए जारी लीज खनन की क्षमता खत्म हो गई है। एनजीटी ने खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में टोडारायसिंह उपखंड स्थित लीज की खनन क्षमता बढ़ाने के लिए रिवर को आयोजित जन्मुनवाई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते अधिकारियों को निरस्त कर दी पड़ी। अब निम्न उक्त जन्मुनवाई के लिए पहले सूचना प्रसारित करेगा। ताकि लोग पर्यावरण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। इसके बाद जन्मुनवाई होगी।

खनिज विभाग के मुताबिक टोडारायसिंह उपखंड क्षेत्र में दी गई लीज की खनन क्षमता प्रति साल 33 लाख टन है। अब तक 30 लाख टन खनन किया जा चुका है। अब 3 लाख टन खनन ही बचा है। ऐसे में खनन क्षमता बढ़ाने के लिए

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन्मुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्तें हैं। इसमें पर्यावरण

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप, तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फॉल्ट आ गया। इससे सोप सिटी को भी रहिमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फॉल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जन्मुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन्मुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।

सोहनलाल सुधार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोक

रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

लीज जाह है अभी लीज

पर्यावरण के लिए कागजी खानापूर्ति

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत

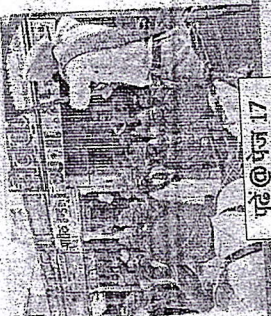


डोंक

पत्रिका

पत्रिका

निवाइ . देवली . मालपुरा . उनियारा . दोडरायसिंह . पीपलू



पढ़ें @ पेज 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक: अधिकारियों को दिए निर्देश

‘बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई’

मशीनों को किया जाए सीज

खाइयों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही मशीनों को सीज किया जाए। बैठक में एडीएम रामरतन सोकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपखंड अधिकारी हुस्मीचंद रोहतानिया मौजूद रहे।



डोंक, अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दूरभाष पर बनेठा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नकों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शहान ए को वन क्षेत्र में गस्त बढ़ाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल आगामी सात दिवस में देने के लिए



पत्रिका
ऑन द
स्पॉट
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patnika.com

डोंक, जिला कलक्टर डॉ. सोम्या झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतते तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लगा सके।

पौधरोपण कार्य की सुनिश्चिता की जाए। इसका प्लान बनाकर प्रस्तुत करें।

नियमानुसार पौध रोपण व बजरी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बलिक बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

अ ए

नटवा

नटवा

स्थित।

आग ए

ईधन र

रामकर

रखा च

24.12.18

26/5/25

सेवामे,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी जीरा.प. नि. म., बून्दी (रा.प.)

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
 प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।
2. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नहीं करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नहीं करने से स्पष्ट है कि एसोसिएट्स ने सी.ई. सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डों की खुली अवहेलना है। इस कारण से



//2//

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसियट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
4. यह कि उक्त एसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दृष्टि से हरे पेड़ों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सड़को का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसियट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्घन्न है।
5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवेध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसियट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवांड

//3//

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड़ कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़ कर करना होता है, नहीं कर रहा है सी.ई.सी का उल्घन्न है।
7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रुक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्घन्न है।
8. खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलियन टी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन 8.2 मिलियन टी.पी.ए. के लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरुद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी की स्वीकृति नहीं दी जाए।

दिनांक : 26/5/25

 प्रार्थना

समीर - 32 - 28मान -

सोलाह की गली - का भूमि -

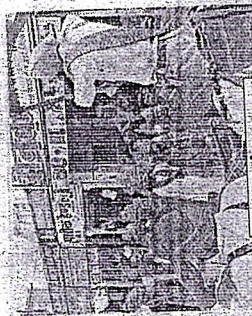
बाजार (दो क)

7737363738

डोंक

पत्रिका

निवाई . देवली . मालपुरा . उनियारा . टोंडायासिंह . पीपलू



पढ़ें @ पेज 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक: अधिकारियों को दिए निर्देश

‘बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई’



पत्रिका
आर्द्र
संपाद

पत्रिका चूज नेटवर्क
patrika.com

डोंक. जिला कलक्टर डॉ. सोम्या झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्टर कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सह नलाल सुथार को निर्देश दिए कि

डोंक. अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दुरभाव पर बनेठा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नक्कों पर विशेष चौकसी बरतने

के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शाइन ए को वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल आगामी सात दिवस में देने के लिए

मशीनों को किया जाए सीज

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही मशीनों को सीज किया जाए। बैठक में एडीएम रामरतन सौकरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद रोहलानिया मौजूद रहे।

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतने तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लगा सके।

पौधरोपण कार्य की सुमिश्रिता की जाए। इसका प्खान बनाकर प्रस्तुत करें।

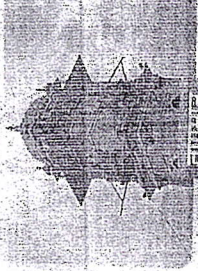
अ ए

खाइयों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

सरकार ने बजरी लीज के लिए एक दर्जन से अधिक शर्तें लगा रखी हैं। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। नियमानुसार पौध रोपण व बजरी से निकलने वाले छोटे कंकड़ों से जहां खनन किया गया उसे समतल किया जाना था। लेकिन ना तो पौध रोपण नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बल्कि बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

नटपा
नटवा
स्थित।
आए
इधन
रामकर
रखाच

पत्रिका



32° अधिकतम
24° न्यूनतम

वर्षा (अधिकतम)
हवा की गति: 26.0 किमी/घंटा

मौसम साफ रहने की संभावना
(सित-मौसम केंद्र टोक)

अक्षा	उंचा	मध्यम	खतरा
0-50	51-100	101-200	201-300
301-400	401-500		

रिडर्स कनेक्ट

हमें भेजें

ई-मेल: patrika@patrika.com
वॉट्सएप: 9660-439374

पढ़ें ज्यूस/हलचल
हलचल/हलचल



समसे जुड़े
[facebook.com/patrika.tmk](https://www.facebook.com/patrika.tmk)

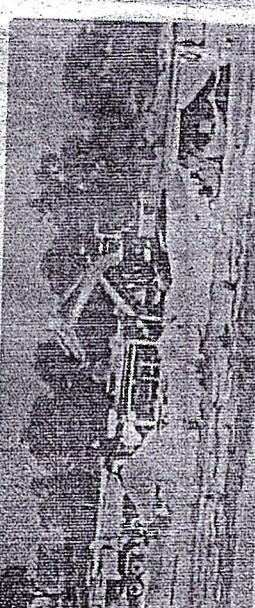
आगामी हलचल

क्षमता बढ़ाने के लिए बगैर सूचना जन सुनवाई को तो लोगों ने जलाई नाराजगी

अब तो बाख़्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्म, एनजीटी ने लगाई रोक

टोडारायसिंह क्षेत्र में चला रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्म होने के कारण पर है। ऐसे में त्यक्षमता से अधिक खनन नहीं करने पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमासुराजसुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लेगा बैठक



टोक, टोडारायसिंह क्षेत्र स्थित बनास नदी में किया जा रहा खनन।

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।

सीडनवाला सुथार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोक

जनसुनवाई की सूचना किसी को नहीं दी। अधिकारी कुछेक लोगों के साथ आ गए। इससे लोगों में नाराजगी है। लीज शर्तों की पालना भी नहीं हुई।

रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

लीज में लीज समाप्त हो चुकी है। टोक में अब करीब 40 हजार टन बजरी का भंडारण शेष है। इससे बजरी की आपूर्ति की जा रही है।

जनसुनवाई के मुताबिक अभी टोडारायसिंह और उनियारा उपखंड क्षेत्र में ही बजरी की लीज जारी है। जबकि टोक, पीपलू, देवली और

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन सुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्तें हैं। इसमें पर्यावरण

महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो हरियाली पर काम किया गया और ना ही जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। शर्तों की पालना भी कागजों में ही चल रही है।

इसके चलते बनास नदी खाइयों में तब्दील हो गई है। खनन के निधारीत मापदंडों की अवहेलना की गई। स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिला।

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप, तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फॉल्ट आ गया। इससे सोप सिटी को भी रहिमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फॉल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com
पटनाई, कस्बे सहित क्षेत्र में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ली।



हवि गौतम की सामूहिक आरती मोके पर श्री गुर्जर गोड ब्राह्मण कास समिति अध्यक्ष जगमोहन गौतम नवयुवक मंडल अध्यक्ष गौतम गौतम समाज के कई रहे।

प्लाई बाधित

होने थडोली फिल्टर प्लांट से सप्लाई बंद करवाई। टीम ने युड लीकेज ठीक करने का काम शुरू गाम तक मरम्मत पूरी होने की है।

कर्मल बैसला की पुण्यतिथि मनाई

बाई वीर गुर्जर छात्रावास में पबीसी आरक्षण के संयोजक रहे मेल किरोडी सिंह बैसला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। माज के लोगों ने कर्मल बैसला ने याद करते हुए उनके पदचिह्न चलने का आह्वान किया। कहा कि समाज में अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, कर्ज मुक्त जीवन और ली-लिखी मां जरूरी है। कर्मल बैसला ने समाज को नई दिशा दी। भोज समाज की प्रगति उन्हीं की है। सभा में प्रधान रामअवतार

श्री मीनेष भगवान की जयंती मनाई

टोक मीना समाज के आराध्य देव श्री मीनेष भगवान की जयंती मीणा छात्रावास एवं अध्ययन संस्थान टोक में सोमवार को मनाई गई।

इस मौके पर भगवान श्री विष्णु के अवतार की जयंती के अवसर पर मीणा समाज की ओर से समाज के विकास एवं उत्थान पर चर्चा भी की गई। तुलसीराम मीणा

नंदकिशोर पुत्र घासी, घासी माली, हनुमान पुत्र रामनिवास, स्वप्न सरकार पुत्र अर्हण सरकार, रामफूल, श्रवण पुत्र जगन्नाथ और रामेश्वर के नाम शामिल हैं। जलदाय विभाग ने सभी को नोटिस दिया है। अवेध नल कनेक्शन को लेकर जलदाय की टीम लगातार जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्खा नहीं जाएगा। पैनल्टी वसूली जाएगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।

कर्मल बैसला की पुण्यतिथि मनाई

लांगडी, वीर गुर्जर छात्रावास संस्था के अध्यक्ष रामभजन गुर्जर, मांगीलाल गुर्जर, शंकर पडियार, शंजोरीराम फौजी, महामंत्री गिरिराज गुर्जर, रामकिशन बहादुरपुरा, देवनारायण गुर्जर, रामकिशन जीवली मौजूद रहे। श्रीगुरु कृपा कार्यालय में भी कर्मल बैसला की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष अशोक लांगडी ने बताया कि कर्मल साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्री मीनेष भगवान की जयंती मनाई

ने बताया कि आगामी एक वर्ष की अवधि में मीणा छात्रावास के अंधूरे भवन निर्माण का कार्य पूरा कर इसे गरीब व होनहार बच्चों के लिए संचालित कर दिया जाएगा। जयंती के मौके पर लड़लाल, कमलेश, हेमराज भरतलाल, गिराज, आशाराम, राजेन्द्र, अशोक आदि मौजूद रहे।

अभियेक आर शांति धारा को पार्श्वनीय भगवान के हा संभस ज्यादा भक्त हैं। आगम के अनुसार सभी तीर्थकर समान होते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundl
 E-mail: rorpcb.bundl@gmail.com

No. RPCB/RO Bundl/PUB-134/3223 Date: 26/03/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स, एम. एल. नम्बर-8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कैंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहंडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथसिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानगयवाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोक द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेण्ड (माइनर मिनेरल) माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स सेण्ड एम. एल. नम्बर-8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारणान, कैंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहंडा, रलावता, ठाठा, सैंतीवास, जेथसिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटियान, मोरडा, मोडियाला, छानगयवाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- चूंकि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन, मध्य दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाय में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आदेश की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :- (i) कार्यालय जिला कलक्टर, टोक। (ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोक। (iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग क्षेत्र, जिला टोक। (iv) संचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोक। (v) उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, भारत जिला टोक। (vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कर्मल संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) जयपुर। (viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कर्मल संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) जयपुर। (ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2025 (शनिवार) को स्थान-पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

26/5/25

सेवामे,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी जी,
रा. प्र. नि. म., बून्दी (राज.)

विषय :- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति में लोन सुनवाई में प्रार्थी की और से आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।
 प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 दिनांक 07.05.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम.एल. को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में स्वीकृति दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाये जाने हेतु लो आपत्तियां मांगी गयी है। जिस पर प्रार्थी की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसियट ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुए पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।

2. यह कि उक्त एसोसियट ने माईनिंग स्वीकृति के नियमों की पालना नहीं करते हुए कोई वृक्षारोपण नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये गये हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि की गयी नियमों में वृक्षारोपण नहीं करने से स्पष्ट है कि एसोसियट ने सी.ई. सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया गया है नदी के किनारे वृक्षा रोपण करना आवश्यक है इसलिए आपत्ति जाहीर करता हूँ व मापदण्डों की खुली अवहेलना है। इस कारण से

लगातार.....2



//2//

माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पेरामीटर के अनुसार कम्पनी एसोसिएट नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पेरामीटर के विपरीत जाकर 100 मीटर तक नदी में गहरी खाईया तब्दील कर रहा है, जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जाए। सी.ई.सी. के नियमों का उल्लंघन है।
4. यह कि उक्त एसोसिएट द्वारा टोंक व टोडा क्षेत्र में स्थिति कृषि भूमि में से फसलों को खराब करते हुए अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडा क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होता है क्योंकि किसानों द्वारा लगायी जाने फसलों का नुकसान होता है तथा पर्यावरणीय दृष्टि से हरे पेड़ों व पोधों को नुकसान पहुचाया जाता है तथा आम राहगीरों के वास्ते बनायी गयी सड़को का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से भी उक्त एसोसिएट को स्वीकृति रद्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। सी.ई.सी. के नियमों का उल्लंघन है।
5. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वालों प्राईवेट कृषि आराजीयात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता बल्कि विभाग व उक्त एसोसिएट की मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़

//3//

किया जा रहा है। इस कारण से भी यह आपत्ति पेश की जा रही है।

6. खनन पानी में कर रहा है खनन 45 पेरामीटर छोड़ कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़ कर करना होता है, नहीं कर रहा है सी.ई.सी का उल्लंघन है।
7. खनन के उपरांत जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे की पानी का बहाव रुक रहा है जिससे सी.ई.सी का उल्लंघन है।
8. खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है सीमा से अधिक खनन कर रहा है 2025 वर्ष में 3.0 मिलियन टी.पी.ए. स्वीकृति है मैसर्स चांडक एसोसियट द्वारा बजरी खनन की स्वीकृति से अधिक बजरी खनन 2 मिलियन टी.पी.ए. (आ.ओ.ए.के) लिए स्वीकृति मांग रहा है जो नियम विरुद्ध है व सी.ई.सी के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए आपत्ति जाहिर करता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मैसर्स चांडक एसोसियट को बजरी खनन हेतु एन.जी.टी. की स्वीकृति नहीं दी जाए।

दिनांक :- 26/5/2025

सहस्र - 3 फुट

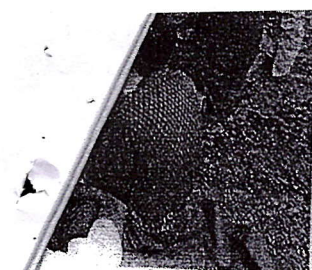
प्रार्थी

J. K. Singh
26/5/25

नाम - केशव राज सिंह

पता - न्यू मधवीर नगर, सड़क के
बायाँ की गली, टोंक (राज.)

M-7014471095



यों को अंतिम रूप दिया।
राजस्थान सरकार व रात 9 बजे
आशीर्वाद समारोह होगा।

कथा का आयोजन



वाले श्रीराम महायज्ञ की तैयारी तेज हो गई है। श्री जोड़ना बालाजी बालापुरा मेहरू में 14 से 22 मई तक इक्कीस कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ होगा।
बुधवार को मंदिर परिसर में यज्ञ कर्ता सत याज्ञिक संग्राट श्री श्री 1008 श्री मुनेश्वर दास महाराज

महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश शुरू 15 जून तक होगा

द्वितीय महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी से दसवीं तक प्रवेश 15 जून तक लिए जाएंगे।

16 जून को प्राप्त आवेदन की सूची विद्यालय बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। 17 जून को लाटरी निकाली जाएगी। 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की अंतिम सूची बोर्ड पर लगाई जाएगी। 19 जून से प्रवेश शुरू होगा। 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी।

तीर्थ की बैठक



अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूज्यनीय माताजी **धर्मती चम्पा देवी** (धर्मपत्नी : स्व. श्री गोकुलचन्द जी जैन) का स्वर्गवास दिनांक 07 मई 2025 को हो गया है।
जिनकी **तीर्थ की बैठक** 09 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 9 से 10 बजे तक जैन मन्दिर मेहन्दवास पर रखी गई है।
नोट : यह बैठक अंतिम बैठक होगी।

शोकाकुल

महेश्वर प्रसाद, बाबुलाल, धर्मचन्द, भैरुलाल (देवर), प्रकाशचन्द, डालचन्द, मोटालाल, विमल, किमलचन्द, गुरेश, अशोक, परस, पवन कुमार, संजय कुमार (पुत्र), अनिल, अक्षय, रिषभ, मस्क (पौत्र), कनिष्क (पौत्र) एक समस्त गार्ग परिवार, अरनिया नील वाले मेहन्दवास मो. 9950612128, 9929600105
श्रीहर पक्ष : श्रीमान नैमीचन्द जी, धर्मचन्द जी, विनोद कुमार जी, पिन्दू जी टोरडी वाले मालपुरा

इसापाना का अध्यक्षता में आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गईं सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
इस मौके पर मेहरू बालापुरा खेड़ा मलका नगर वन का खेड़ा मलुवारी की ढाणी, जनकपुरा तितरिया, रामेश्वरपुरा छीपट की

के गावा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महायज्ञ में काशी जनकपुर अध्याया वेदावन मथुरा सहित कई आश्रमों से साधु-संत आएंगे। 18 मई को शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। महायज्ञ के दौरान श्रीराम कथा और शाम को रासलीला का आयोजन किया जाएगा।


Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
 E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/261 Date : 07/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बाइक एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012 खनन क्षेत्र 1260.86 हेक्टेयर निकट, ग्राम नुरासिया, राजस्थान धारणान, केवराबास, चन्दापुरा, सोलगायाबास, गोलाहडा, रलावता, ठावा, सुतीबास, जयलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भादिया, मोरडा, सोडियाला, कानमराबासपुरा, बरबास एवं घुली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड संपद (मार्डन गिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे इधर, पंचायत समिति समागा, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी अग्रे सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-134/232 दिनांक 26/03/2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित में दिनांक 01/04/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 01/04/2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2. चूंकि उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अतिरिक्त कारणों से अभिन आदेशों तक स्थगित की गई जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-134/232 दिनांक 03/05/2025 द्वारा जारी कर रही दैनिक अखबार टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित में दिनांक 05/05/2025 व दैनिक भास्कर (टोंक भास्कर) में दिनांक 05/05/2025 को प्रकाशित की गयी।

3. चूंकि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07/05/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गई है।

4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006, संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित आपत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अधिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

- कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
- कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
- कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
- पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।
- उपपरबन्ध अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक।
- क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना स्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, स्थानिक क्षेत्र, झालाना द्वारा, जयपुर।
- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुन्दी, जिला बुन्दी।
- कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के संशोधित आदेश क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18617 दिनांक 07.05.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 (सोमवार) को स्थान पंचायत समिति समागा, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सूचना में लिखित आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुन्दी, जिला बुन्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

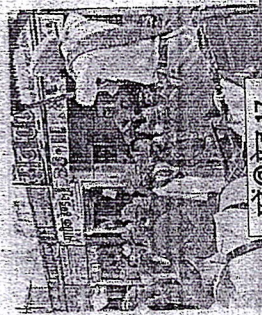
भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.स., बुन्दी

CLASSIFIED

BhaskarAd.com
Classified Ad ऑनलाइन बुक करें
Call: 9772019222

दैनिक पत्रिका

निवाँ . देवली . मालपुरा . उनियारा . तोडारायसिंह . पीपलू



पृष्ठ 17

जिला कलक्टर ने ली बैठक : अधिकारियों को दिए निर्देश

‘बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर बरती जाए विशेष चौकसी, सख्ती से हो कार्रवाई’



पत्रिका
ऑनलाइन
पत्रिका
patika.com

डॉक. जिला कलक्टर डॉ. सोमया झा ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन की रोकथाम के लिए शुक्रवार को कलक्टर कक्षा में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खनिज विभाग के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को निर्देश दिए कि



डॉक. अधिकारियों की बैठक लेती जिला कलक्टर।

वे राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उपखंड अधिकारी उनियारा को दूरभाष पर बनेवा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं पत्थरों के परिवहन को रोकने के लिए बनाए गए नार्को पर विशेष चौकसी बरतने

के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला वन अधिकारी मरिय शइन ए को वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। जिला कलक्टर ने सहायक खनिज अभियंता को धारा 177 के तहत दर्ज प्रकरणों की समस्त डिटेल्स आगामी सात दिवस में देने के लिए

भाषीनों को किया जाए सीजा

जिला कलक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी संगता राम वर्मा को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के उपयोग में ली जा रही

प्रशासन को मिल रही है शिकायतें

बजरी व पत्थर खनन की शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही है। इसके चलते जिला कलक्टर ने बजरी व पत्थर के अवैध खनन पर विशेष चौकसी बरतने तथा सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खनन माफिया पर अंकुश लगा सके।

पौधरोपण कार्य की सुनिश्चिता की जाए। इसका प्लान बनाकर प्रस्तुत करें।

खाइयों में बदली नदी, नियमों की पालना में अनदेखी

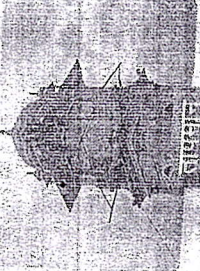
सरकार ने बजरी लीज के लिए एक दर्जन से अधिक शर्तें लगा रखी हैं। लेकिन खनिज विभाग ने बनास नदी में इन शर्तों की अनदेखी बरती है। नियमानुसार पौध रोपण व बजरी से निकलने वाले छोटे कंकड़ों से जहां खनन किया गया उसे समतल किया जाना था। लेकिन ना तो पौध रोपण नजर आ रहा और ना ही खाइयों को भरा गया। बल्कि बनास नदी में नियम विरुद्ध बेतहाशा खनन करने से इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है।

अ ए

नटवा
नटवा
स्थित।
आगर
इधन
रामका
रखा च



सहर मौसम



32° 24°
अधिकतम न्यूनतम

वर्षा 66% (अधिकतम)
हवा की गति 26.0 किमी/घंटा

मौसम साफ रहने की संभावना
(सोप-मौसम केन्द्र टोक)

पल्सशन चर (AOP)	
टोक	82 30%
अक्षा	0-50
मध्यम	51-100
उच्च	101-200
उत्तरार्ध	201-300
उत्तरार्ध	301-400
उत्तरार्ध	401-500

रीडर्स कोन्वर्ट
हमें भेजें

समस्या सुझाव

कोडिंग पॉडकैस्ट

ई-मेल: tonk.sah@patrika.com
वॉटरमार्क: 9660-439374

पूरे जगत्वा खबरें
देख फालो/वीडियो

patrika.com/tonk-news
क्यूआर कोड को
मोबाइल से
करें स्कैन

हमसे जुड़ें
facebook.com/patrika.tonk

हामी हलचल

क्षमता बढ़ाने के लिए बरस पूरना जन सुनवाई की तो लोपाई नाराजी

अब तो बरख्शो... बनास नदी में लीज खनन की क्षमता खत्तम, एनजीटी ने लगाई रोक

टोडारायसिंह क्षेत्र में चल रही लीज की बजरी खनन क्षमता खत्तम होने के कारण पर है। ऐसे में त्य क्षमता से अधिक खनन नहीं करते पर एनजीटी ने रोक लगाई है। क्षमता से अधिक खनन तब ही किया जाएगा जब नियमानुसार जनसुनवाई में क्षेत्र के लोगों की अनुमति हो।

खनिज विभाग अब फिर से स्थानीय लोगों तथा विभागों के अधिकारियों की लोपाई बैठक



टोक. टोडारायसिंह क्षेत्र स्थित बनास नदी में किया जा रहा खनन। पर्यावरण विभाग ने खनिज विभाग के साथ टोडारायसिंह के पंचायत समिति सभागार में आमजन की जन सुनवाई कार्यक्रम तय किया था। ताकि पर्यावरण को लेकर मिलने वाले सुझाव तथा किसी कोई आपत्ति नहीं होने पर खनन की क्षमता बढ़ा दी जाए। लेकिन जन सुनवाई में लोग नहीं पहुंचे। जब इसकी जानकारी कुछेक जनप्रतिनिधियों को मिली तो वे पहुंचे और बिना सूचना जन सुनवाई करने पर नाराजी जताते

टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी लीज में खनन की क्षमता बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की जानी थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया। ऐसे में जन सुनवाई निरस्त हो गई। सूचना प्रसारित करने के बाद फिर से बैठक होगी।

सहेनलाल सुथार, सहायक अभियंता खनिज विभाग टोक

जन सुनवाई की सूचना किसी को नहीं दी। अधिकारी कुछेक लोगों के साथ आ गए। इससे लोगों में नाराजगी है। लीज शर्तों की पालना भी नहीं हुई।

रामचन्द्र गुर्जर, जनप्रतिनिधि टोडारायसिंह

नदी जगह है उभी लीज

खनिज विभाग के मुताबिक सभी टोडारायसिंह और उभियारा उपखंड क्षेत्र में ही बजरी की लीज जारी है। जबकि टोक, पोपलू, देवली और

पर्यावरण के लिए कागजी खानापूर्ति

स्थानीय जन प्रतिनिधि रामचन्द्र गुर्जर समेत अन्य ने जन सुनवाई में कहा कि बनास नदी में दी गई लीज के साथ एक दर्जन से अधिक शर्तें हैं। इसमें पर्यावरण

इसके चलते बनास नदी खाइयों में तब्दील हो गई है। खनन के निर्धारित मापदंडों की अवहेलना की गई। स्थानीय लोगों को रोजगार तक नहीं मिला।

सोप में तेज हवाओं से 14 घंटे बिजली गुल, लोग बेहाल

सोप. तेज हवाओं के चलते कस्बे की 33 केवी लाइन में सोमवार को बड़ा फाल्ट आ गया। इससे सोप सिटी को भी रहिमनगर फीडर की 3 फेस लाइन में फाल्ट आ गया। सुबह 10:15 बजे बिजली गई, जो दोपहर 1 बजे

बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पलार्ड. कस्बे सहित क्षेत्र में सालवार को अचानक मौसम ने करवट ली।

5 FEB 2015

तापारण्य ग्राम पंचायत, छाण बास सूर्या

पंचायत समिति, टोड़ारायसिंह (जिला-टोंक) राज०

प्रेषक : श्रीमती सन्तरा देवी गुर्जर सरपंच, ग्राम पंचायत छाण बास सूर्या	 राज्यपाल जयते	प्रेषित :- श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
--	--	--

क्रमांक: 544

दिनांक: 26/05/2015

विषय- निधियों के विभिन्न अवैध खनन कर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का क़त्त

महोदय विषय के नाम निवेदन है/बनास नदी के किनारे के कारण नदी में गहरे गड्ढे बनने का कारण

① मै. फडक एत० के द्वारा बनास नदी के 15 से 30 फुट गहरे गड्ढे खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया

② कीना सीमावर्ती के सम्पूर्ण नदी के से बग़री उठा ली

③ नदी के आस पास के गांवों की सम्पूर्ण सड़के शीतल कर दी

④ शीतल के अनुसार नदी किनारे पर पेड व घास ज़रूरी

लगाई रुकन कार्य के लीज में फिल्लर लगाना आवश्यक है/इसके बग़ैर लगाया/जो निषेध विरुद्ध है/

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

JEECP
21/5/25

विषय— मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग— विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 बून्दी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई है। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश है :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई वृक्षा रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लंघन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

RECEIVED
20/5/25

ग्राम पंचायत बोदुन्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :

शिला राजकुमार मीणा

प्रशासक

ग्राम पंचायत बोदुन्दा

प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :- माननीय

श्रीमान् टोडारायसिंह जी शर्मा

मुख्यमंत्री राजस्थान

सरकार

क्रमांक : 8P/25-26/27.5.2025/597)

दिनांक 27.5.2025

विषय : मेक्सर्स-चाँडक एलेक्ट्रिक एम. एल. की मॉडरिनिंग हेतु पर्यावरण त्वीकृति में जन-सुनवाई में जनार्ण की और से मापन प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग - विज्ञापन संख्या RPB/RO पञ्जाब / RPB-134/26/दिनांक 26.5.27 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार एवं उम्मेद्वर मेक्सर्स-चाँडक एलेक्ट्रिक एम. एल. की मॉडरिनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु त्वीकृति पूर्व मैल्वीकृति की गई थी तथा अब मॉडरिनिंग प्रक्रिया बढ़ाते जाते हैं ताकि बाधितों मांगी गयी हो जिस पर जनार्ण की और से जनहितार्थ निम्न प्रकार कार्यवाही प्रस्तावित है:-

1. यह कि उम्मेद्वर एलेक्ट्रिक ने पूर्व में मॉडरिनिंग कीमतों की सूची तय से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार से पूर्व रूप से धारा बढ़ाने के पर्यावरण अधिकारों का हनन किया।

शिला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदुन्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम पंचायत बोदुन्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :

शिला राजकुमार मीणा

प्रशासक

ग्राम पंचायत बोदून्दा

प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :-

माननीय

श्रीमान्

राजलाल जी अर्मा

मुख्यमंत्री राजस्थान

जयपुर

क्रमांक : 98/25-26/5098/2025/12

दिनांक 27/5/25

लेश्वर... 2.

2. यह कि डमर एलेक्जिप्ट ने माइनिंग लीज के नियमों की पालना नहीं की है और कोई सुरक्षा नहीं किया है और ना ही किसी तरह से पेड़-पौधे लगाये जाये हैं जो कि पर्यावरण की हानि की सभी नियमों में सुरक्षा नहीं करते हैं यह है कि एलेक्जिप्ट ने सी.डी.सी. के नियमों के नियमों का पालन नहीं किया जाता है न ही के बिना सुरक्षा सुरक्षा आवश्यक है इसलिए आपसे जाहिर करना है व आपसे से जुड़ी जानकारी है। हम कारण से माइनिंग डमर लीज रद्द किया जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है।

3. यह कि माइनिंग लीज के मापदंडों परामर्श के अनुसार डमर लीज एलेक्जिप्ट नहीं है और तब सुरक्षा माइनिंग सुरक्षित है परन्तु डमर परामर्श के बिना जो 100 मीटर तक नहीं है जहाँ सुरक्षा तब सुरक्षा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है इस आधार पर लीज नहीं दी जाए। सी.डी.सी. के नियमों का इन्फ्रिंग है।

शिला राजकुमार मीणा
प्रशासक
ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम पंचायत बोदून्दा
प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :

शिला राजकुमार मीणा

प्रशासक

ग्राम पञ्चायत बोर्ड-न्दा

प.स. टोडारायसिंह (टॉक)

मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :

श्रीमान्.

2114

मेजरम लाल जी शर्मा

मुंबई मे ३१ जून १९५७

क्रमांक: ११/२५-२९/५०९९/२७.५.२५

दिनांक 27.5.27

अ. नं. 3

4. यह कि हमर हेलेसिएर अथ हांड व टोप ग्रेज में लिपि कि
बुकि में से फसलों की खयब फुरे हुए इन धाकि रूप से बड़ी
का खयब फुर आवगमन क्रिय भय है म्योकि किमानों का लगायी
जाने फसलों का नुकसान होला है तथा पयानरणीय इच्छि है
पेड़ों व पेड़ों की नुकसान पहुचाया जाय है तथा आम गहरी के
वाले बनायी गयी लड़के का पूर्ण रूप से नुकसान क्रिया पधारहा
है। हम काळ से भी हमर हेलेसिएर की लीपि रद्द क्रिया जाना
उन्कि हवे आम संगत है। सी. ई. सी. के निम्न का कथन

५. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर स्वयं विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अंगत नहीं लायी जाती है तथा अनेक मामलों में जिनसे जाने वालों पर वेक सुवि आरापीयात पर वेंडारण में पटक गयी किमा जमा बलित विभाग व उम्ह हसो विर भी मिलि अगर से आम जनता के दनारम व पयावख के साथ मिलवा।

साथ दिनांक

मजाला - १०० रु

शीला राजकुमार मीणा
अधीक्षक

प्रशासक
ग्राम पंचायत बोडुन्दा
प. स. टोडारायसिंह (टोंक)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोलन्दा

ग्राम पंचायत बोदून्दा

पंचायत समिति, टोडारायसिंह (टॉक)

प्रेषक :

शिला राजकुमार मीणा

प्रशासक

ग्राम पंचायत बोदून्दा

प.स. टोडारायसिंह (टॉक)

मो. 8290440508, 9660644499

प्रेषिता :-

माननीय

श्रीमान

मदन लाल जी शर्मा

मुख्यमंत्री राजस्थान

क्रमांक :

११/६०००/२५-२८

११/४/११

दिनांक

२७.५.२५

- जिना कर रहा है। हम कुछ भी नहीं यह आपसे प्रेष की कर रहे हैं
६. खून पानी में कर रहा है खून ५५ बेरामीर को कर रहे हैं
 मैं किसानों के कुशों से को कर रहा होगा है नही कर रहा
 है सी. ई. सी. का उल्लंघन है
७. खून के इफर जमीन से समतल करना होगा है क्योंकि
 पानी का बहाव नही इसके जमीन समतल नही कर रहा है
 जिससे की पानी का बहाव कर रहा है जिसके सी. ई. सी. का
 उल्लंघन है
८. खून कार्य के लीक सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है परिसर
 में सीमा से अधिक खून कर रहा है २५-२०२६ तक
 गैजेटिंग (सीमा क्षेत्र) कराना आवश्यक है परिसर में सीमा
 के लोकर द्वारा करनी खून की सीमा में अधिक बड़ी खून
 करी के लोकर कर रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है।
 पर्यावरण स्वीकृति नही है परिसर आपसे जाहिर कर रही है।
 उर: पार्श्वना पत्र प्रेष कर निवेदन है कि मेरे पास लोकर करी बड़ी खून है
 एन. पी. टी. की स्वीकृति नही की जाए।

शिला राजकुमार मीणा
 प्रशासक

ग्राम पंचायत बोदून्दा
 प.स. टोडारायसिंह (टॉक)
 राजस्थान

दिनांक: २७.५.२५

ग्राम पंचायत बोदून्दा
 प.स. टोडारायसिंह (टॉक)
 राजस्थान

CS

066(P)
22/5/25

पंचायत विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत मोरभाटियान

पंचायत समिति टोडारायसिंह, जिला टोंक (राजस्थान)

प्रेषक

निर्मला देवी बैरवा

प्रशासक, ग्राम पंचायत मोरभाटियान

पंचायत समिति टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज.)

फो 9414579738

प्रति

श्रीमान मुख्यामत्री महोदय,

राजस्थान - सरकार

जयपुर (राज.)

पत्रांक : का.पा.प./मोरभाटियान/

दिनांक 22/5/2025

विषय :- वनास नदी में बजरी खनन से पदचिह्न स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि मैं चाण्डल एनोसिमेंट म.ल. की माइनिंग से पदचिह्न स्वीकृति की आवश्यकता लेनिन कम्पनी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है न पैड पैसे लग जा रहे हैं तथा उ मीटर से ज्यादा खनन कर रहा है तथा आम की सारी रुइके तोड़ दी हैं उनकी मालूम नहीं की है नदी में ज गहरे गड्ढे कर दिम है तथा परमिशन से अनधिक क्षेत्र में खुदाई रहा है जिससे पेयजल का स्तर गिर रहा है

इस महोदय को निवेदन है कि चाण्डल एनोसिमेंट को अवैध माइनिंग की अनुमति नहीं दी जावे।

सादर

मेरी गुप्त पंचायत के गुप्त मोरठा मोरठा हिमन व मोरठियाल में वन्य खनन की स्वीकृति नहीं दी जावे।

अनंदा

प्रशासक

ग्राम पंचायत मोर भाटियान
पंच.टोडारायसिंह, जि.टोंक(राज.)

JEECP
25/5/25

कार्यालय ग्राम पंचायत खरेडा प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :-

गायत्री देवी शर्मा

प्रशासक

ग्राम पंचायत खरेडा

मोबा.

प्रेषिती :-

श्रीमान

मुख्यमंत्री महोदय

राज. हरदो

जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक :- 26.5.2025

सेवाये

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

विषय- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग- विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 यूँन्दी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियाँ मांगी गई हैं। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियाँ पेश हैं :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई भी क्षति रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तयदील कर रहा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लंघन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

- क्योंकि किसानों द्वारा लगाये जाने फसलों को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेंड व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरों के वास्ते बनाई गई सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को भिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ थिलवाड किया जा रहा है।
 5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़कर करना होता है जो नहीं कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुकने जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है।
 6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनों तरफ के प्रमुख, पुलों, राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रेत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।
 7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टॉक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 वृन्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह, तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों, पत्राकारों की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गालाहंडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मारभाटियान, मोरडा, माडियाला, छाणवासनूर्या, वरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टॉक राज0 के गांवों को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से सिर्फ तीन-चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40-50 लोगों को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिएट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवों में कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
 8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी०ई०सी० के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण प्रयावरण स्वीकृति नहीं दी जावे, बजरी खनन हेतु एन०जी०टी० की स्वीकृति नहीं दी जावे। *ग्राम खरीका व जयलपट्टा एम० ए० पी० दे गो० ई०*

५१६१

ग्रामपन्नी

प्रशासक
ग्राम पंचायत खरेडा
पंचायत समिति टोडारायसिंह

प्रशासक ग्राम पंचायत बरसी

पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

JEEP
24/5/25

प्रेषक :

श्रीमती सन्तरा देवी

प्रशासक

ग्राम पंचायत बरसी

पं.स. टोडारायसिंह जिला टोंक

मोबा. 9829713383, 6378846123

प्रेषित :

श्रीमान मुख्यमंत्री महो.

राज. स. सरकार

जयपुर

क्रमांक

श्रीमान्. मुख्यमंत्री महोदय,

राजस्थान सरकार

जयपुर राज०

दिनांक 26/5/25

विषय- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी०पी०ए० से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी०पी०ए० तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।
प्रसंग- विज्ञापन संख्या आर०पी०सी०बी० / आर०ओ० बून्दी पी०यू०बी० 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई हैं। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई वृक्षा रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी०ई०सी० के नियमों का उल्लंघन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है



- क्योंकि किसानों द्वारा लगाये जाने फसलों को नुकसान होता है तथा पर्यावरण क्षति से हरे पेड़ व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आगराहरीयों के चारों तरफ गई सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जवाब नहीं दिया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
 5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़कर करना होता है जो नहीं कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुकें जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है।
 6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनों तरफ के प्रमुख, पुलों, राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।
 7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टॉक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह, तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों, पत्रकारों की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाछेडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेधलिया, राधावल्लभपुरा, मोरमाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणवाससूर्या, बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टॉक राज0 के गांवों को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये है जिनमें से सिर्फ तीन-चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40-50 लोगों को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिएट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवों में कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई द्वारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
 8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी0ई0सी0 के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है इस कारण पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जावे, बजरी खनन हेतु एन0जी0टी0 की स्वीकृति नहीं दी जावे।

उक्त प्रकार के कुंदीफा गाम गोलेडा बलावता हा/हा, किलेवाड बनास के किनारे बसने जो मेरी काम क्षमता के गोलेडे।

114

प्रशासक

ग्राम पंचायत बस्सी
प.स. टेडारायसिंह, टोंक

TEECR
22/05/25

कार्यालय ग्राम पंचायत कंवरावास प.स. टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :-

रामपाल गुर्जर

उप प्रशासक

ग्राम पंचायत कंवरावास

मोबा. 7229851771

प्रेषित :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

राजस्थान सरकार

जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक :- 26/5/2025

शेयार्थे,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज०

विषय- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी०पी०ए० से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी०पी०ए० तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रसंग- विज्ञापन संख्या आर०पी०सी०बी० / आर०ओ० यून्दी पी०यू०वी० 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम०एल० को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई हैं। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अपहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई वृक्षा रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी०ई०सी० के नियमों का उल्लंघन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलों को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है।

क्योंकि किसानों द्वारा लगाये जाने फसलों को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड़ व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरों के वास्ते बनाई गई सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को ज़ब्त नहीं किया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़कर करना होता है जो नहीं कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुकने जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है।
6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनों तरफ के प्रमुख , पुलो , राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।
7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह , तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों , पत्राकारों की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता , ठाढा , सैतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा , मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या , बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवों को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से सिर्फ तीन-चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40-50 लोगों को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिएट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवों में कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त चांडक एसोसिएट्स द्वारा सी०ई०सी० के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस कारण प्रर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जावे, बजरी खनन हेतु एन०जी०टी० की स्वीकृति नहीं दी जावे। हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम सालग्यावास, कंवरावास, चन्दपुरा, व बनेडियाचारणान गांव है जहाँ अवैध खनन होता है।

4/57



उप प्रशासक
ग्राम पंचायत कंवरावास
पंचायत समिति टोडारायसिंह

सेवामें,

श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज0

JEECP
27/5/25

विषय— मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।
प्रसंग— विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 बून्दी पी0यू0बी0 134 / 261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई हैं। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं :-

1. यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धता बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई वृक्षा रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
2. यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकती है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तबदील कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लंघन है।
3. यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसलो को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

क्योंकि किसानों द्वारा लगाये जाने फसलों को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड़ व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरों के वास्ते बनाई गई सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जब्त नहीं किया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़कर करना होता है जो नहीं कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है।
6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनों तरफ के प्रमुख, पुलों, राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रेत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।
7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह, तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों, पत्राचारों की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाढा, सैतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणबाससूर्या, बरवास, एवं झूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवों को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से सिर्फ तीन-चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40-50 लोगों को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिएट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवों में कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

(जिला पारामिट्र)
EX - मोडल इंस्ट्रुमेंट मोर (अप)
9950517372 रत्नावता 8290603141
रत्नावता

(अपमो 6110/002/2017)

(वरवारा)
(9929972733)

छोटी रत्ना मोर
रत्ना रत्ना
मो (मो रत्ना)

कालशम रत्ना रत्ना
8920220676

रत्ना रत्ना
9829777851

मो रत्ना रत्ना
मो रत्ना
8696174304

रत्ना रत्ना
मो रत्ना रत्ना
रत्ना रत्ना

रत्ना रत्ना
मो रत्ना रत्ना
9521298254

रत्ना रत्ना (रत्ना रत्ना रत्ना)
(रत्ना रत्ना रत्ना)
9784824709

सह (४)
(३)
२६/५/२५

कार्यालय पंचायत समिति टोडारायसिंह (टोंक)

प्रेषक :-

सीता देवी गुर्जर

प्रधान

पंचायत समिति टोडारायसिंह

मोबा. 9414081210

प्रेषिती :-

श्रीमान मुख्यमंत्री महो.

राज सरकार मध्य

क्रमांक :-

दिनांक :- 26.5.25

सेवा में,

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर राज 0

विषय- मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 द्वारा उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक करने हेतु माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई दिनांक 26.05.2025 की ओर से आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत है।
प्रसंग- विज्ञापन संख्या आर0पी0सी0बी0 / आर0ओ0 यून्डी पी0यू0बी0 134/261 दिनांक 07.05.2025 के संदर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मैसर्स चांडक एसोसिएट्स एम0एल0 को माईनिंग हेतु टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी खनन हेतु स्वीकृति पूर्व में दी गई थी तथा अब माईनिंग क्षमता बढ़ाई जाने हेतु लोक आपत्तियां मांगी गई हैं। जिस पर आम जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से जनहितार्थ निम्न प्रकार आपत्तियां पेश हैं :-

- यह कि उक्त एसोसिएट्स ने पूर्व में माईनिंग की शर्तों की पूरी तरह से अंगेहलना की है तथा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से धरा बताते हुये पर्यावरण अधिकारी का हनन किया है। माईनिंग शर्तों के नियम की पालना नहीं करते हुये कोई भी रोपण नहीं किया है। इस कारण माईनिंग क्षमता स्वीकृति रद्द किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।
- यह कि माईनिंग स्वीकृति के मापदण्डों पैरामीटर के हिसाब कम्पनी एसोसिएट्स नदी क्षेत्र में 3 मीटर तक खुदाई माईनिंग कर सकरी है परन्तु उक्त पैरामीटर के विपरीत जाकर 10 मीटर नदी में गहरी खाया तयदीन कर रखा है जिससे पर्यावरण को पूर्ण रूप से खराब किया जा रहा है। यह सी0ई0सी0 के नियमों का उल्लंघन है।
- यह कि उक्त एसोसिएट्स द्वारा टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि में से फसली को खराब करने हेतु अवैधानिक रूप से बजरी का खनन कर आवागमन किया जाता है जिससे आये दिन टोंक व टोडारायसिंह क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है

व्योकि किसानों द्वारा लगाये जाने फसलों को नुकसान होता है तथा पर्यावरण दृष्टि से हरे पेड़ व पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तथा आमराहगीरों के वास्ते बनाई गई सड़कों का पूर्ण रूप से नुकसान किया जाता रहा है। इस कारण से उक्त एसोसिएट्स को माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

4. यह कि आम जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती है तथा अवैध रूप से किये जाने वाले प्राईवेट कृषि आराजियात पर भण्डारण को जप्त नहीं किया जाता है बल्कि उक्त एसोसिएट्स को मिली भगत से आम जनता के स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
5. यह कि खनन पानी में किया जाता रहा है खनन 45 पैरामीटर छोड़कर नियमों में किसानों के कुओं को छोड़कर करना होता है जो नहीं कर रहा है। खनन के उपरान्त जमीन को समतल करना होता है क्योंकि पानी का बहाव नहीं रुके जमीन समतल नहीं कर रहा है जिससे कि पानी का बहाव रुक रहा है। खनन कार्यों के लीज सीमा में पिल्लर लगाना आवश्यक है नहीं लगा रहा है।
6. यह कि नदी के जल स्तर से नीचे खनन कार्य किया जा रहा है तथा दोनों तरफ के प्रमुख, पुलों, राजमार्गों से एक किलोमीटर दायरे में रैत व बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपस्ट्रीम की तरफ पुल या सार्वजनिक नागरिक संरचना (पानी के सेवन बिंदुओं सहित) के पांच गुना दायरे में और डाउनस्ट्रीम की तरफ 10 गुना दायरे में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है।
7. यह कि दिनांक 26.05.2025 को ए0डी0एम0 टोंक क्षेत्रीय अधिकारी आर0पी0सी0डी0 बून्दी, एस0डी0एम0 टोडारायसिंह, तहसीलदार टोडारायसिंह व अन्य अधिकारियों जनप्रतिनियों, पत्राकारों की उपस्थिति में लोक जनसुनवाई में 17 राजस्व गांव कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधाबल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणवाससूर्या, बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 के गांवों को मिलाकर कुल 59 व्यक्तियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये थे, जिनमें उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति भी रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से सिर्फ तीन-चार ही व्यक्ति ही प्रभावित गांव के मौजूद थे उक्त एसोसिएट्स ने लोक जनसुनवाई में अपने काम करने वाले 40-50 लोगों को लेकर जनसुनवाई की खानापूर्ति करने के लिए जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित हो गये। क्योंकि उक्त एसोसिएट्स द्वारा उक्त प्रभावित गांवों में कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण आम जनता की अनुपस्थिति के कारण लोक जनसुनवाई दुबारा करवाकर उक्त एसोसिएट्स की माईनिंग स्वीकृति रद्द किया जाना उचित व न्यायसंगत है।
8. यह कि यदि मैसर्स चांडक एसोसिएट्स द्वारा पूर्व में जारी 3.0 मिलियन टी0पी0ए0 से बढ़ाकर 8.2 मिलियन टी0पी0ए0 तक बजरी खनन करने हेतु अनुमति दी जाकर एवं माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो आम जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त चांडक एसोसिएट्स का भारी विरोध किया जाकर जनआन्दोलन किया जावेगा जिस कारण यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं प्रशासक की रहेगी।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि उक्त वाडक एसोसिएट्स द्वारा सी0ई0सी0 के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है इस कारण प्रयावरण स्वीकृति नहीं दी जावे, बजरी खनन हेतु एन0जी0टी0 की स्वीकृति नहीं दी जावे।

(116)
26/5/2025
दिनांक

स्तीता
प्रधान
पंचायत समिति टोडारायसिंह
जिला टोक (राज.)
आम जनता

9414081210
वामनचंद्र 13/5/25
श्री मल्लिकार्जुन

कुरास्या, बनेडियाचारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोरभाटियान, मोरडा, मोडियाला, छाणवाससूर्या, बरवास, एवं चूली तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0

9982838150
D.R.
देवराज भीम टोडारा
जिला परिषद
राजस्थान
9950517372
रलावता
EX-20507 मल्लिकार्जुन मोर (BP)
रलावता 8290603149

मल्लिकार्जुन
(मल्लिकार्जुन)

मल्लिकार्जुन
(मल्लिकार्जुन)
(9729772733)

चीतर रलावता
9829777851

मो. 8290603149
मो. 9950517372
मो. 9982838150

कालराज सैतीवास
8920220676

मो. 8290603149
मो. 9950517372
8696174304

राजेश मो. 11
मल्लिकार्जुन
BP मो. 1

मल्लिकार्जुन
मो. 8290603149
9521298254

मल्लिकार्जुन (मल्लिकार्जुन)
(मल्लिकार्जुन)
9784824709

साकर स्वागत किया, महिलाओं ने भजन गाए निकाली, पहले दिन का महात्म्य बताया

समाज के सारथी

इस सप्ताह... निष्काम गो सेवा संस्थान

टोडारायसिंह में निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान असहाय गायों की सेवा कर रहा

संस्था के बारे में ... बीमार, असहाय और एक्सीडेंटल गोमाताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है।

उद्देश्य ... गोमाता को फिर से सम्मान दिलाना। लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक सहयोग करें।



टोंक। श्रीमदभागवत कथा को लेकर कलशयात्रा निकाली गई।

राम नाम का महत्व बताया, नशा मुक्ति का संदेश



पंचेवर | कुराड़ के स्याह गांव स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में राम सभा हुई। सभा में राम नाम के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम संयोजक विक्रम सिंह ने बताया कि रामद्वारा जयपुर के आदि संत सतगुरु सुखराम महाराज के कैवल्य ज्ञान-विज्ञान का

प्रचार-प्रसार किया गया। यह प्रवचन स्वयं सेवक हरीश सिंह ने दिया। हरीश सिंह ने बताया कि राम सभा किसी भी जाति या समाज का व्यक्ति करवा सकता है। यह पूरी तरह निःशुल्क होती है। सिंह ने कहा कि राम नाम के सुमिरन से सभी दुखों का नाश होता है।

टोडारायसिंह | कस्बे में स्थित निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान जहां बीमार, असहाय और एक्सीडेंटल गोमाताओं की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। साल 2020 में शुरू हुए इस संस्थान से अब तक तीन हजार से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं।

ये युवा 100 किलोमीटर दूर तक घायल या बेसहारा गोमाताओं को एंबुलेंस से लाकर इलाज करते हैं। संस्थान की शाखाएं अब अन्य जिलों में भी सक्रिय हैं। संस्था के सुनिल पारीक ने बताया कि जयपुर रोड पर स्थित इस केंद्र में फिलहाल 150 जखमी गोमाताओं की सेवा हो रही है। अब तक करीब 8000 गोमाताओं का इलाज किया जा चुका है। संस्थान में वेटेनरी की पढ़ाई कर चुके युवा भी सेवा दे रहे हैं। सभी सेवादर एक समान भाव से काम करते हैं। संस्थान किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। सेवा के साथ-साथ गोरक्षा भी इन युवाओं की प्राथमिकता है। संस्थान जनता के दान से चलता है। यहां राधा-कृष्ण और कांकरा बालाजी के सान्निध्य में सेवा होती है। गोमाता की पीड़ा को दूर करने के लिए ये युवा हर हद पर करने को तैयार रहते हैं।



गायों के उपचार की व्यवस्था - गो चिकित्सालय में दो एंबुलेंस हैं। जिनमें जखमी गायों को लाया जाता है। गोशाला के पास दो एंबुलेंस हैं। एंबुलेंस में वेटेनरी डॉक्टर, मेडिकल किट, गोमाता उठाने के ट्रैक्स उपलब्ध हैं। गोशाला में एक आईसीयू वार्ड बना हुआ है। जहां वेटेनरी उनका उपचार करते हैं। दवाई का 1 माह का खर्चा लगभग 60 हजार रुपए आता है। इसी प्रकार लगभग 4 लाख रुपए माह में सभी मर्दों में खर्च हो जाता है।

चारे की व्यवस्था - गायों के लिए चारे की व्यवस्था आमजन के सहयोग से होती है। कई बार खेतों से चारा भर कर लाना पड़ता है। कई बार दयालु लोग स्वयं पैसे खर्च कर डलवा देते हैं।

यहां संपर्क करें

निष्काम गो सेवा तंत्र संस्थान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 8302968796, 6377986774 पर संपर्क किया जा सकता है।

न विश्वकर्मा की प्राण-प्रतिष्ठा हुई

वाले परिवारों ने क्रम से प्रतिष्ठा का लाभ लिया। बृजमोहन जांगिड़ कैथूदा ने तीन लाख एक हजार रुपए की बोली लगाकर प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया गया। शिखर पर दंड और ध्वजा भी रोहण की गई। हरिहरात्मक पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाआरती हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। यज्ञ कराने वाले आचार्य और पंडितों का मंदिर समिति ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। आचार्य पंडित शास्त्री ने विधिवत महोत्सव सम्पन्न करवाया। कार्यक्रम में देवली-उनियारा विधायक

राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि भारत की भूमि भगवान राम और कृष्ण की पावन भूमि है। जब-जब पाप बढ़ा, भगवान ने भारत में जन्म लिया। विधायक गुर्जर ने सामुदायिक भवन के लिए दस लाख रुपए देने की घोषणा की। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने मंदिर में पांच लाख रुपए से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में रामगोपाल सुथार, राकेश जांगिड़, घनश्याम पंवार, राजेन्द्र गुर्जर, सरोज नरेश बंसल, बट्टीलाल बिडौली, परमेश्वर जांगिड़, अमोलक जांगिड़, हनुमान प्रसाद जांगिड़, विष्णु जांगिड़ सहित कई लोग मौजूद रहे।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com
No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/232
Date : 03/05/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स चांदक एसोसिएट्स, एम.एल.नम्बर - 8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरासा, बनेडिया चारणान, कंवरावास, चन्दपुरा, सालगावास, गोलाहेड़ा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटिया, मोरझा, मोडियाला, छानमयवासपुरा, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की रिवरबेड सेज्ड (माईनर मिनरल), खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 Million TPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.05.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान - पंचायत समिति सभागार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/18553 दिनांक 02.05.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।

2. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है। भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

हे रहे हैं श्रद्धालु

भास्कर CLASSIFIED

BhaskarAd.com
Classified Ad प्रतिलिखित नुक़्त करे
Call : 9772019222

TANT"
acceptance of advertising
its contents. The Indian
held responsible for such
damage incurred as a
companies, associations or
spapers or Publications.
that readers make
sending any monies or
nts with advertisers or
tisement in any manner

51. Maharashtra, India.
ormerly Known as M/s. Adani Housing
Corporate Affairs, herein after refer to
on of loan dues from borrower/s, in the
will be done by the undersigned through

Notice Date	Reserve Price (RP)
	EMD
Bidding Amount (red debt)	Bid Increase Amount
13-May-24 Rs. 95252/- As On Date 09-May-24	Rs.900000/- Rs.90000/- Rs.1000/-
12-Aug-24 Rs. 156051/- As On Date 09-Aug-24	Rs.1570000/- Rs.157000/- Rs.1000/-
e: ICICI BANK D, IFSC Code: ICIC0000106	
M	
ri - 9001607018	

ending bidders should make their own
erty, prior to submitting their bid. The
ank. The property is being sold with all
not be responsible in any way for any
a bid. The inspection of property/ies put
word can be obtained free of cost by
T in the account mentioned above.
e following documents uploaded in the
d Draft; ii) Copy of PAN Card; iii) Proof
id is liable to be rejected. UPLOADING
DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO
documents, Trainings/ Demonstration on
medabad 380 009, Gujarat, India E-mail
6354910183 Karan Modi - 7016716557.
1491, e-mail ID: ajay.kumar2@tyger.in

d in Point No.4)] on/ before **04-May-25**
e eligible for participating in the e-Auction

or its multiple and in case bid is placed
ne till the closure of e-Auction process),
sure of the e-Auction Process shall be

ccessful bidders shall be refunded. The
e EMD already paid, within 24 hours of
such extended period as agreed upon
unt already deposited by the offer shall
property/ amount.
e-Auction. Neither the Authorised Officer/
e that they are technically well equipped

utory/ non-statutory dues, taxes, rates,
t any or all offer(s) or adjourn/ postpone/
/s. i-Sourcing Technologies Pvt. Ltd.,
nce Pvt. Ltd nor Service provider will be
ted to make all necessary arrangements
uction successfully.

nd ancillary expenses before the date of

Sd/-
Authorised Officer
per Home Finance Private Limited



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)
राष्ट्रिय/क्षेत्रीय कार्यालय/पंचायत-412/3399
Date: 27-03-2025



LIFE
Lifestyle for
Environment

पर्यावरणीय स्वीकृत समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोय मीणा प्लॉट संख्या 222 ग्राम आकरोल द्वारा मैसनी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टोपीए (आर.ओ.एम.)
1.	सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोय मीणा, खसरा संख्या 901/663	प्लॉट संख्या 222	1.6885	आकरोल	मैसनी स्टोन	125050
2.	श्री हरफूल चौधरी	12/2022	4.5021	आकरोल	मैसनी स्टोन	620250
3.	श्री हरफूल चौधरी	07/2022	2.1428	आकरोल	मैसनी स्टोन	246000
4.	श्री हरफूल चौधरी	08/2022	1.0697	आकरोल	मैसनी स्टोन	121500

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.4031 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1112800 टोपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम आकरोल, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर से संबंधित प्राचीन पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां पंचायत बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि सुश्री प्रियंका मीणा पुत्री श्री सोमोय मीणा प्लॉट संख्या 222 ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनाय उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील कार्यालय बिजयनगर, जिला-ब्यावर।
6. ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पत्र क्रमांक कब्बा/एफ-8/ (14)/सामान्य/2025/777 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 05.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(निधि खण्डलवाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpch.bundi@gmail.com



LIFE
Lifestyle for
Environment

No. RPCB/RO Bundi/PUB-134/3223
Date: 26/03/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसरी चांदक एसोसिएट्स, एम. एल. नम्बर-8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारगान, केंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटिया, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रिवरबेड सेज्ड (माइनर मिनरल) माइनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता विस्तार **3.0 Million TPA (ROM)** से **8.2 Million TPA (ROM)** हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसरी चांदक एसोसिएट्स सेज्ड एम. एल. नम्बर-8/2012, खनन क्षेत्र 1260.96 हेक्टेयर निकट ग्राम कुरास्या, बनेडिया चारगान, केंवरावास, चन्दपुरा, सालग्यावास, गोलाहेडा, रलावता, ठाठा, सैतीवास, जेथलिया, राधावल्लभपुरा, मोर भाटिया, मोरडा, मोडियाला, छानमयबाससूर्या, बरवास एवं चूली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का विस्तार 3.0 MillionTPA (ROM) से 8.2 Million TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसरी चांदक एसोसिएट्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसारण में लोक सुनवाई हेतु इस आयु की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनाय उपलब्ध है :- (i) कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक। (ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। (iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। (iv) पंचायत समिति, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक। (v) उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह, जिला टोंक। (vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरमय भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। (vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। (ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। (x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/14341 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.05.2025 (शनिवार) को स्थान-पंचायत समिति समानगर, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी



BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD
Office of the Chief Engineer (Project), 3rd Floor,
Cauvery Bhavan, K.G. Road, Bangalore - 560 009.

No.:BWSSB/CE(P)/ACE(Cstr&DCW)/2533/2024-25
Date:28.03.2025

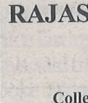
INVITATION FOR TENDER
(Through KPP Portal only)

BWSSB invites tenders from two stage tenders eligible contractors for the work of **Project Monitoring Consultancy for the work of providing water supply feeder main, construction of Ground Level Reservoirs, Over Head Tanks and allied works for Dr. Shivaram Karantha Layout, Bengaluru.**

Amount put to tender: **Rs. 124.40 Lakhs.**
EMD: **Rs. 2.00 Lakhs.**

The last date and time for receipt of completed tenders is on **15.04.2025 upto 15:00 Hrs.** The bids will be opened on **16.04.2025 at 16:00 Hrs.** The details regarding the tender and participation in the e-procurement process can be obtained by logging on to <https://kppp.karnataka.gov.in> For further details contact undersigned office during the working hours.

DIPR/CP/JA/6000/2024-25
Sd/- Chief Engineer(Project)



RAJASTHAN STATE HIGHWAYS AUTHORITY, UNIT-JODHPUR

Toll Rate List for
Collection of User Fee on Bhavi-Pipar-Khimsar Highway (SH-86C)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भावी पीपाड़-खींवर (राज्य राजमार्ग-86C) किमी 0.00 से 97.00 किमी में उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनो पर प्रत्येक शुल्क ग्राम घणामराया यथा किमी 3.00, ग्राम नाडोतेड़ा यथा 48.000 किमी ग्राम मेरिया यथा 85.700 किमी पर स्थित टोल प्लाजाओं की संशोधित प्रत्येक उपयोगकर्ता शुल्क दरे (₹) दिनांक 01.04.2025 से विमानानुसार है।

Bhavi-Sathin Section of SH-86C TP-1 (Ghanamagra)
Effective from 01.04.2025

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	45	65	1475
2	LCV, LGV or Mini Bus	65	100	2245
3	Bus or Truck	135	200	4425
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	220	330	7370
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	265	400	8845

Sathin-Palri Ranawata Section of SH-86C TP-2 (Nadatoda)

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	50	75	1700
2	LCV, LGV or Mini Bus	80	115	2590
3	Bus or Truck	155	230	5095
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	255	380	8490
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	305	460	10190

Palri Ranawata-Khinwsar Section of SH-86C TP-3 (Mangaria)

S. No.	Category of Traffic	Revised rates for the FY 2025-26 (for single journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for Return journey)	Revised rates for the FY 2025-26 (for multiple journey)
1	Car, jeep, Van or LMV or Tractor with trolley carrying Non Agriculture produce	40	60	1300
2	LCV, LGV or Mini Bus	60	90	1980
3	Bus or Truck	115	175	3900
4	HCM Or EME or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	195	290	6495
5	Oversized vehicles (7 or More axles)	235	350	7795

3. किसी टोल प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर रहने वाले गैर वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी के लिए 300 रूपए मासिक दर पर इस राजमार्ग की एक निर्दिष्ट खण्ड को उपयोग करने के लिए पास बनाए जा सकेंगे जो इस राज्य राज मार्ग के दूसरे टोल प्लाजा से पहले तब मान्य होगा।
4. शुल्क के दरे सदस्य (डबल्यू, सी वी ओ), राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित की गयी है।

Sd/- (Alok Malvia)
General Manager (Tech.) cum Project Director
Rajasthan State Highway Authority, Jodhpur
No. PD/RSJA/JDP/SH-86C/2024-25/D-837, Date: 27.03.2025

Jaipur

